



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]
No. 187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2006/श्रावण 13, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2006/SRAVANA 13, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2006

अंतिम जांच परिणाम

विषय : सिंगापुर से डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (पीएचपीजी बेस)
के आयात विषयक मध्यावधि पाटनरोधी समीक्षा जांच

सं. 15/14/2005-डीजीएडी.- क. मामले की पृष्ठभूमि : जबकि 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 20 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं. 51/1/2001-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन. गण. तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएचपीजी बेस (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किया था। अनंतिम जांच परिणाम दिनांक 5 जून, 2002 को जारी किए गए थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क दिनांक 5 जुलाई, 2002 को लगाया गया था।

और जबकि संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 122/2002-सीमाशुल्क दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 द्वारा लगाया गया था।

2. जबकि नियमावली में प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की समय-समय पर समीक्षा की अपेक्षा की गई है और यदि वे उन्हें प्राप्त सकारात्मक सूचना के आधार पर सन्तुष्ट हैं कि ऐसा शुल्क लगाना जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से इसे वापस लेने की सिफारिश कर सकते हैं । उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी किसी हितबद्ध पक्ष से समीक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए सकारात्मक सूचना के प्रस्तुतिकरण के आधार पर प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जानी अपेक्षित है, बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद उचित समयावधि बीत गई हो, कि क्या पाटन की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क लगाए रखना जरूरी है, कि क्या शुल्क हटाने अथवा परिवर्तित करने अथवा दोनों स्थितियों में क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है ।

उपर्युक्त प्रावधान की शर्तों के अनुसार उत्पादक तथा निर्यातक मेसर्स कनेका सिंगापुर कार्पोरेशन, सिंगापुर (केएससी) ने परिवर्तित परिस्थितियों में, इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा का अनुरोध प्रस्तुत किया है ।

3. सिंगापुर के संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक एवं निर्यातक मेसर्स कनेका सिंगापुर कार्पोरेशन (केएससी), सिंगापुर ने परिवर्तित परिस्थितियों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित आधार बताए हैं :-

- भारत को केएससी की निर्यात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है ।
- सीमाशुल्क 35% से घटाकर 20% कर दिया गया है ।
- पाटन मार्जिन में उल्लेखनीय गिरावट आई है और इस प्रकार मूल जांच में निर्धारित बेंचमार्क में तदनुसार कमी की जानी चाहिए ।
- कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे सामान्य मूल्य में कमी आई है ।

- कंपनी को हुए लाभ में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो सामान्य मूल्य में गिरावट प्रदर्शित करता है ।

4. आवेदक द्वारा प्रदत्त सकारात्मक जानकारी को देखते हुए, जिसमें परिवर्तित परिस्थितियों की ओर संकेत करते हुए इस समय लागू उपाय की समीक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर ऊपर उल्लिखित नियम 23 के प्रावधान के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित माना है । दिनांक 20 सितंबर, 2002 की अधिसूचना सं. 51/1/2001-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी ने नियमावली की शर्तों के अनुसार यह समीक्षा करने के लिए जांच शुरू की कि क्या सिंगापुर (जिसे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएचपीजी बेस के आयातों पर शुल्क जारी रखना पाटन को प्रभावहीन करने के लिए आवश्यक है, कि क्या शुल्क हटाने अथवा परिवर्तित करने अथवा दोनों स्थितियों में क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है ।

ख प्रक्रिया:

5. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई :
 - (i) समीक्षा प्रारंभ करने के बाद प्राधिकारी द्वारा नियम 6(4) के अनुसरण में अपेक्षित जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को तथा भारत स्थित घरेलू उद्योग को जांच प्रारंभ अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भिजवाई गई;
 - (ii) नियम 6(2) के अनुसरण में संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को जांच प्रारंभ करने की सूचना दी गई और उनसे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर भिजवाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया ।

- (iii) नियम 6(4) के अनुसरण में आवश्यक जानकारी मंगाने हेतु भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निर्यातकों तथा प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भिजवाई गईं ।
- (iv) दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि (पीओआई) के लिए जांच की गई । तथापि, क्षति की जांच 2000-01 से जांच अवधि के अंत तक की अवधि हेतु की गई ।
- (v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से विगत तीन वर्षों तथा जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी आंकड़ों के संकलन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया ; तथापि इस जांच में डीजीसीआई एंड एस की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया गया है क्योंकि यह देखा गया कि मात्रा के रूप में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत निर्यात मात्रा काफी अधिक है ।
- (vi) मेसर्स कनेका सिंगापुर कार्पोरेशन (केएससी) तथा मेसर्स कनेका जापान, जापान (केएनके) को छोड़कर अन्य किसी निर्यातक से जांच प्रारंभ अधिसूचना का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । जांच में बाद के चरणों में घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्ष ने जांच प्रारंभ अधिसूचना का किसी प्रकार से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।
- (vii) वर्तमान जांच में जहां तक सुसंगत हो, विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त सभी विचारों तथा प्रस्तुतियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है ।
- (viii) विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गैर गोपनीय पाठ को प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया गया और हितबद्ध पक्षों के निरीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया है ;
- (ix) घरेलू उद्योग को हुई क्षति की, जहां तक संभव हो, जांच करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई ।

- (x) नियमावली के अनुसार सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु प्राधिकारी द्वारा विषय की समीक्षा के प्रयोजनार्थ सहयोगी निर्यातकों एवं आवेदनकर्ता के आंकड़ों का भी सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात् सत्यापन रिपोर्ट की प्रति टिप्पणी हेतु निर्यातकों को भिजवाई गई और उनसे प्राप्त टिप्पणियां अंतिम जांच रिपोर्ट में शामिल कर ली गई हैं। अन्य सभी हितबद्ध पक्षों की जानकारी के लिए गैर गोपनीय सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सार्वजनिक रूप में भी रखी गई।
- (xi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए दिनांक **3 फरवरी 2006** को सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि, संबद्ध देशों के संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक उपस्थित थे। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षों से मौखिक रूप में व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जांच के लिए जिस सीमा तक सुसंगत पाया गया, हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित विचारों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम में विचार किया गया है। ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में इस जांच रिपोर्ट में जिन अनिवार्य तथ्यों/आधारों पर विचार किया गया है उनसे हितबद्ध पक्षों को दिनांक 14 जुलाई, 2006 को अवगत कराया गया और इस संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में विधिवत विचार किया गया है।
- (xii) अधिसूचना में **** हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना प्रदर्शित करता है, जिसे नियमावली के तहत विचार करने के बाद प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं "समान वस्तु":

6. मूल जांच तथा वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (पीएचपीजी बेस) है, जो उपर्युक्त उल्लिखित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 की पहली अनुसूची तथा आईटीसी एचएस वर्गीकरण के तहत शीर्ष सं. 2942.00 के अंतर्गत

आता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा किसी भी प्रकार से, वर्तमान जांच के दायरे पर बंधनकारी नहीं है। मुख्य रूप से डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (जिसे ऊपर उल्लिखित पर्यायवाची के अनुसार भी पढ़ा जाए) अर्थात् संबद्ध वस्तु का भारत में आयात किया जाता है, जिसे विभिन्न आयातकों/विनिर्माताओं द्वारा डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लाइसीन मिथाइल पोटेशियम डेन सॉल्ट (जिसे एतदपश्चात् पीएचपीजीडीएस कहा गया है) में स्वस्थाने परिवर्तित करके एमॉक्सिलीन तथा सीफेड्रोक्सिल (अर्थात् बल्क ड्रग) के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। अन्य शब्दों में एमॉक्सिलीन के उत्पादन में पीएचपीजी का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। जब पीएचपीजी को पीएचपीजीडीएस में परिवर्तित कर लिया जाता है तभी उसका उपयोग एमॉक्सिलीन आदि के उत्पादन में किया जाता है। यह परिवर्तन या तो पीएचपीजी/पीएचपीजीडीएस के विनिर्माताओं द्वारा अथवा प्रयोक्ताओं अर्थात् एमॉक्सिलीन आदि के उत्पादकों द्वारा किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद के बारे में कोई तर्क नहीं है। जहां तक समान वस्तु का संबंध है, नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित और वहां बेचे जा रहे पीएचपीजी बेस में कोई उल्लेखनीय भिन्नता नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित पीएचपीजी बेस भौतिक विशेषताओं, कार्यों व प्रयोगों, विनिर्देशनों, वितरण एवं विपणन, प्राइसिंग तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। उपभोक्ता संबद्ध देशों से आयातित पीएचपीजी बेस का उपयोग कर सकते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा आयातित पीएचपीजी बेस के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी बेस सिंगापुर (संबद्ध देश) से आयातित पीएचपीजी बेस के समान उत्पाद माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग:

8. मूल जांच में आवेदन मेसर्स दौराला ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, दौराला, मेरठ (उ.प्र.), जिसका विलय अब मेसर्स श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट: दौराला ऑर्गेनिक्स, दौराला में हो गया है, द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आवेदनकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और घरेलू

उद्योग के रूप में समीक्षा जांच में उन्होंने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के अर्थ के भीतर, मेसर्स डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि., यूनिट: दौराला ऑर्गेनिक्स, दौराला (डीओएल अथवा दौराला आर्गेनिक्स) घरेलू उद्योग है।

ड विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्क एवं प्राधिकारी द्वारा जांच:

9. घरेलू उद्योग का कहना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा समीक्षा का आधार अपर्याप्त है। मेसर्स डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि., यूनिट-दौराला ऑर्गेनिक्स, दौराला, मेरठ (उ.प्र.) (जिसे पहले मेसर्स दौराला आर्गेनिक्स लि., दौराला, जिला मेरठ (उ.प्र.) के नाम से जाना जाता था) तथा घरेलू उद्योग (जिसे एतदपश्चात् डीआई कहा गया है) ने कहा है कि संबद्ध सामग्री डी (-) हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (जिसे एतदपश्चात् पीएचपीजी बेस भी कहा गया है) से संबंधित मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब मामलों की अंतिम जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी और सिंगापुर तथा चीन से संबद्ध सामग्री के आयात पर सीमाशुल्क अधिसूचना सं.122/2002 दिनांक 31.10.2002 जारी करके पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, तब से संबद्ध सामग्री डी (-) हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (जिसे एतदपश्चात् पीएचपीजी बेस भी कहा गया है) से संबंधित मूल स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
10. डब्ल्यू.सी.ओ. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 में पाटनरोधी लेवी की समीक्षा हेतु निम्नलिखित बातें निहित हैं :
 - (i) जहां आवश्यक हो, प्राधिकारियों द्वारा शुल्क लगाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।
 - (ii) किसी हितबद्ध पक्ष के अनुरोध पर, जो समीक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है।

- (iii) जहां, पाटन को प्रभावहीन करने के लिए शुल्क लगाना जारी रखना जरूरी हो ।
- (iv) यदि शुल्क हटाया अथवा परिवर्तित किया जाता है अथवा दोनों स्थितियों में, क्या क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है ।
11. घरेलू उद्योग का कहना है कि पीएचपीजी बेस की मांग एवं आपूर्ति के संबंध में भारत के बाजारों में व्याप्त स्थिति तथा घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति से शुल्क लगाने की मध्यावधि समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । आगे यह भी कहा गया है कि समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड इस बात से संबंधित है कि यदि शुल्क हटाया अथवा परिवर्तित किया जाता है अथवा दोनों स्थितियों में क्या क्षति जारी रहने अथवा पुनः होने की संभावना है । अनुच्छेद 11.2 के अनुसार समीक्षाएं संदर्शी स्वरूप की होती हैं, जिसमें यदि निश्चयात्मक शुल्क हटा दिया जाता है, तो पाटन तथा क्षति पुनः होने की संभावना का प्रक्षेपण करना अपेक्षित है । इसमें पाटन आयातों के स्तर, कीमतों तथा घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर भविष्य की परिकल्पनिक घटनाओं का प्रतितथ्यात्मक विश्लेषण करना अपेक्षित है । इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है कि क्या शुल्क उठा लेने से घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की संभावना है ।
12. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी कहा है कि उन्होंने अपने कार्य-निष्पादन के बारे में प्राधिकारी को दिनांक 15 दिसंबर, 2005 को भेजे गए पत्र में गोपनीय आधार पर आवश्यक तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग को अब भी क्षति हो रही है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में और भी गिरावट आएगी ।
13. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी कहा है कि केएससी द्वारा किए गए निर्यात पर पाटन मार्जिन न्यूनतम होने का दावा किया गया है जबकि केएससी के निर्यात के संबंध में निर्यात के पहुंच मूल्य तथा पाटन मार्जिन दोनों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, अतः बेंचमार्क घटाया जाना चाहिए । केएससी ने दावा किया है कि निविष्टियों के आयात के पहुंच मूल्य में

उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसका अर्थ यह है कि निर्यात मूल्य में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे केएससी ने भी स्वीकार किया है और ऐसी स्थिति में पाटन मार्जिन कम होने के बजाए बढ़ेगी, जैसा कि केएससी का दावा है। जहां तक निर्यात कीमत का प्रश्न है, यह बताया गया है कि कनेका, सिंगापुर से पीएचपीजी बेस की निर्यात कीमत में गिरावट आ रही है, जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि वस्तुओं का पाटन भारतीय बाजार में अब भी हो रहा है।

14. आगे यह भी कहा गया है कि केएससी ने दावा किया है कि कच्चे माल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के कारण उनकी उत्पादन लागत भी कम हो गई है। केएससी का दावा है कि पिछले चार वर्षों में प्रमुख कच्चे माल की कीमत लगभग 25% घट गई है। सूचकांक आधारित अनेबन्ध-9 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 की तुलना में 7 कच्चे माल की कीमतों में 2005 के दौरान 2% से 17% गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में 8 कच्चे माल की कीमतें 5 से 53% बढ़ गई हैं। आगे यह भी कहा गया है कि यह एक ज्ञात तथ्य है कि पिछले 1-2 वर्षों में अपरिष्कृत तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 2001 में लगभग 25 अमरीकी डॉलर/बैरल से हाल की अवधि में 70 अमरीकी डॉलर/बैरल हो गया है। इसके कारण न केवल सॉल्वेंट की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, अपितु उपयोगी वस्तुओं की लागत भी उक्त समय में लगभग दोगुनी हो गई है। यदि इसमें मजदूरी तथा अन्य ऊपरी व्यय में 5% की मामूली वृद्धि भी जोड़ दी जाए, तो उत्पादन लागत कम से कम 10 से 15% और बढ़ जाती है। व्यय में 5% की सामान्य वृद्धि का दावा केसी की वित्तीय वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट से और भी पुख्ता होती है जिसमें कहा गया है कि "बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय (एसजीएंड ए) 85,673 मिलियन येन था, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.3% अधिक था।"
15. घरेलू उद्योग का कहना है कि केएससी द्वारा पीएचपीजी बेस पीएचटीएन उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चा माल अपनी पितृ कंपनी केनिका कार्पोरेशन, जापान-(केसी) से प्राप्त किया जाता है। केएससी के लिए पीएचटीएन की लागत ही पीएचपीजी बेस की उत्पादन लागत में लागत का प्रमुख घटक है। तदनुसार कुछ समय बाद ऊपर उल्लिखित कारकों

जैसे सॉल्वेंट, उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों, मजदूरी लागत आदि में वृद्धि होने से पीएचपीजी बेस की उत्पादन लागत में पीएचटीएन की लागत निश्चित रूप से बढ़ेगी। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से केसी द्वारा उत्पादित पीएचटीएन की लागत संरचना का विवरण प्राप्त करने और पीएचटीएन की लागत संरचना और केसी से केएससी में पीएचटीएन के अंतरण मूल्य तंत्र का विस्तृत सत्यापन करने का अनुरोध किया है।

16. घरेलू उद्योग का कहना है कि केएससी का यह अभिमत कि केनिका का निर्यात मूल्य उत्पादन लागत से अधिक है तथा कंपनी द्वारा अर्जित मुनाफे में गिरावट आई है, परस्पर विरोधी है। यदि पहले वे उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री करते थे, तो उन्हें घाटा होना चाहिए था और जब निर्यात मूल्य उत्पादन लागत से भी अधिक है, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, तो मुनाफे में वृद्धि होनी चाहिए थी; जो उनके इस तर्क के विरुद्ध है कि मुनाफा कम हो गया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्होंने भारतीय बाजार में वस्तुओं के पाटन के लिए मूल्य कम कर दिए हैं।
17. इसके विपरीत आवेदनकर्ता का यह कहना है कि निविष्टियों में गिरावट आई है अथवा नहीं; यह एक तथ्य है और यह आवेदनकर्ता कंपनी की सूचना/साक्ष्य/रिकार्ड पर आधारित है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या भारतीय उत्पादक का भी यही अनुभव है। इसके अलावा जहां याचिकाकर्ताओं ने पिछले 4-5 वर्षों में कीमतों में गिरावट की बात की है, वहीं भारतीय उत्पादक ने जांच अवधि और उसके बाद के समय के बीच की बात कही है। इस बात से इंकार नहीं है कि जांच अवधि तथा इसके पश्चात कीमतों में वृद्धि हुई है। पहले की गई जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन भी काफी अधिक था तथा कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी को शामिल नहीं किया गया था। आगे यह भी कहा गया है कि प्रमुख-निविष्टियों के मूल्यों में कमी, उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, रोजगार में उल्लेखनीय कमी, मूल्यहास के कारण लागत में गिरावट आदि के मद्देनजर कंपनी की उत्पादन लागत में गिरावट आई है। कनिका द्वारा पिछली जांच तथा वर्तमान जांच के संबंध में उत्पादन लागत की तुलना का ब्यौरा, जिसका मात्रात्मक कारणों सहित अंतरों में योगदान था,

उपलब्ध कराया गया तथा दौरे के समय इसे सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया गया ।

- (क) अन्य कारणों के साथ, प्रमुख निविष्टि अर्थात् पीएचटीएन के मूल्य में इसलिए गिरावट आई क्योंकि कंपनी ने इसे अधिप्राप्ति स्रोत **** के स्थान पर **** से प्राप्त किया ।
- (ख) चूंकि कनिका ने तथ्यात्मक सूचना प्रदान कर दी है अतः दौराला द्वारा ने गई सामान्य मूल्य संरचना निरर्थक है ।
- (ग) याचिकाकर्ताओं ने न केवल भारत को निर्यात बिक्री की, अपितु तीसरे देशों को भी निर्यात की सौदेवार विस्तृत जानकारी प्रदान की है । यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि क्या कंपनी उत्पाद का पाटन तीसरे देशों में से किसी को कर रही है ।
- (घ) कनिका द्वारा निर्यात पर किए गए व्यय का बीजक दर बीजक विस्तृत ब्यौरा दे दिया गया है, अतः इस संबंध में दौराला के किसी भी दावे को खारिज करना आवश्यक है ।
- (ङ) पिछली जांच में उत्पादन लागत अधिक होने के संभावित कारणों में से एक कारण यह था कि उस जांच अवधि में कंपनी ने उत्पाद का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में किया था, परिणामतः ऊपरी लागत अधिक हो गई ।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

- 18. प्राधिकारी द्वारा इस समीक्षा जांच की शुरुआत के संबंध में हितवद्ध पक्षों की विभिन्न प्रस्तुतियों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है ।
- 19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि प्राधिकारी द्वारा, पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यदि वह उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट

हैं कि ऐसा शुल्क लगाना जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो वह केन्द्रीय सरकार से इसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे।

20. करार के अनुच्छेद 11.2 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी शुल्क लगाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा, जहां आवश्यक हो, अपनी स्वयं की पहल से करेंगे, अथवा हितबद्ध पक्ष, जो समीक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करता हो, के अनुरोध पर करेंगे, बशर्ते निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद समुचित अवधि व्यतीत हो गई हो। हितबद्ध पक्षों को प्राधिकारियों से यह जांच करने हेतु अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या पाटन को प्रभावहीन करने के लिए शुल्क लगाना जारी रखना आवश्यक है, कि क्या शुल्क हटा लेने अथवा परिवर्तित करने अथवा दोनों स्थितियों में क्षति जारी रहने की संभावना है। यदि इस पैराग्राफ के तहत समीक्षा के परिणामस्वरूप प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क अब जरूरी नहीं है, तो इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने की तारीख से एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद हितबद्ध पक्ष के अनुरोध पर समीक्षा शुरू करना एक स्थायी पद्धति रही है और इस अपेक्षा को व्यापार नोटिस 1/99 द्वारा अधिसूचित किया गया था। तदनुसार इस मामले में समीक्षा की शुरुआत पाटनरोधी शुल्क लगाने की तारीख से 26 माह बाद की गई है।

21. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 के तहत समीक्षा के आधार को प्रतिपादित करना अनिवार्य है और याचिकाकर्ता ऐसा करने में असफल रहा है। अतः समीक्षा शुरू करना त्रुटिपूर्ण है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला है कि आवेदनकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत की है कि केएससी की भारत को निर्यात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है और सीमाशुल्क 35% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि पिछले पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है, पाटन मार्जिन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और कच्चे माल की कीमत में कमी के मद्देनजर उत्पादन लागत में आई उल्लेखनीय कमी के कारण सामान्य कीमत में कमी को देखते हुए मूल जांच में

निर्धारित बेंचमार्क में बदलाव किया जाना चाहिए । ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में बदलाव के कारण यह माना गया है कि प्राधिकारी द्वारा मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना उपयुक्त है । प्रकटीकरण विवरण के अलावा घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के मुद्दे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की पर्याप्तता के बारे में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनकी प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है । घरेलू उद्योग का तर्क है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन तथा प्रश्नावली के उत्तरों में पर्याप्त प्रकटीकरण नहीं किया गया है । यह भी बताया गया है कि प्रश्नावली के उत्तरों में सूचीबद्ध जानकारी का अभाव था और कुछ प्रश्नों के गोपनीय उत्तरों में अपर्याप्त जानकारी दी गई । इसके अलावा, आवेदक द्वारा संबंधित कंपनियों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई और निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच अवधि तथा पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें उपलब्ध नहीं कराई गई । प्राधिकारी द्वारा इन तर्कों की जांच की गई और नियम 7 के अपेक्षाओं, उत्पाद की प्रकृति तथा उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में सीमित प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के मद्देनजर तथा इस तथ्य को देखते हुए कि कनेका, सिंगापुर के एकमात्र उत्पादक तथा निर्यातक हैं, यह अभिमत व्यक्त किया जाता है कि आवेदक द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए दावे न्यायोचित हैं । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित पर्याप्त जानकारी आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई । इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि आवेदक ने जून, 04 तथा जून, 05 को समाप्त अवधि एवं जांच अवधि से पिछले तीन वर्षों से संबंधित प्रगति रिपोर्टें गोपनीय आधार (क्योंकि वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं) पर उपलब्ध कराई । इसके अलावा, मैसर्स कनेका, जापान द्वारा न केवल कनेका, जापान कंपनी के संबंध में, परंतु प्रभागों तथा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समूह के बारे में भी विस्तृत वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराई गई । जांच से यह ज्ञात हुआ कि प्रदत्त जानकारी कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों पर आधारित थी, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप पाए गए और इनमें उत्पादन, बिक्री, विचाराधीन उत्पाद की लागत व कीमतों से संबंधित जानकारी उचित रूप से प्रदर्शित की गई थी । विश्वव्यापी स्तर पर संबंधित कंपनियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई । कच्चे माल की लागत एवं कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण का विश्लेषण नीचे दिए गए खंड में किया गया है ।

ड पाटन निर्धारण:

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन

22. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के सामान्य मूल्य से अभिप्रेत है :

- (i) खपत के प्रयोजनार्थ निर्यातक देश अथवा भूभाग में समान वस्तु के लिए व्यापार की सामान्य स्थिति में उप धारा (6) के तहत बने नियमों के अनुसरण में यथा निर्धारित तुलनात्मक कीमत; अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश अथवा भूभाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य स्थिति में समान वस्तु की कोई बिक्री न हो अथवा जब किसी खास बाजार स्थिति के कारण अथवा निर्यातक देश अथवा भूभाग के घरेलू बाजार में बिक्री की मात्रा कम होने की वजह से ऐसी बिक्री से समुचित तुलना न की जा सके तो सामान्य मूल्य
- (क) समान वस्तु का तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य जब निर्यातक देश अथवा भूभाग अथवा समुचित तीसरे देश से निर्यातित हो जो उप धारा (6) के तहत निर्मित नियमों के अनुसार निर्धारित हो; अथवा
- (ख) उद्गम देश में समुचित प्रशासनिक, विक्रय तथा सामान्य लागत तथा लाभ जोड़ते हुए उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, जो उपधारा (6) के तहत निर्मित नियमों के अनुसार निर्धारित हो"

बशर्ते उद्गम देश से अन्य देश में वस्तु के आयात के मामले में और जहां निर्यात देश के माध्यम से वस्तु का मात्र पोतलदान हुआ हो अथवा निर्यात वाले देश में ऐसी वस्तु का उत्पादन न हुआ हो अथवा निर्यात वाले देश में तुलनात्मक मूल्य न हो, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।

सामान्य एवं निर्यात कीमत :

23. प्राधिकारी ने नोट किया है कि मेसर्स केएससी की सिंगापुर में कोई घरेलू बिक्री नहीं है । जहां तक तीसरे देशों में इसकी बिक्री का प्रश्न है, आवेदनकर्ता न्यायोचित आधार के साथ प्रस्ताव नहीं कर सके कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किस तीसरे देश को लिया जाए । तीसरे देशों को बिक्री की जांच के पश्चात् प्राधिकारी स्थायी रूप से अपनाए गए मानदंडों को देखते हुए प्राधिकारी भी सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किसी तीसरे देश का निर्धारण नहीं कर सके । सामान्य मूल्य के निर्धारण के ऊपर संकेतित आधार के अभाव में प्राधिकारी के पास कंपनी द्वारा सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के अलावा और कोई विकल्प नहीं था ।
24. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच तथा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स केएनके, जापान, मेसर्स कनेका सेल्स कार्पोरेशन, सिंगापुर, जो इस जांच में आवेदनकर्ता है, की पितृ कंपनी है । उल्लेखनीय उत्पादन कार्यकलाप के अतिरिक्त केएनके, जापान द्वारा इसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है । इसके अलावा, केएनके, महत्वपूर्ण कच्चे माल की खरीद भी करता है, जो केएनके, सिंगापुर हेतु बेस तथा डेन सॉल्ट के उत्पादन के लिए अपेक्षित है । तथापि, सत्यापन दल को यह दिखा दिया गया कि केएससी सहित किसी भी संबद्ध कंपनी को कोई सेवा निःशुल्क प्रदान नहीं की जाती । यद्यपि यह कारोबार परिपाटी के तौर पर किया जाता है, तथापि ये सेवाएं प्रदान करने से संबंधित लागत केएनके द्वारा रखी गई मार्जिन से कम पाई गई । यह पाया गया कि केएनके ने कच्चे माल की खरीद और केएससी को उसकी आपूर्ति करके एवं केएससी को बेस और डेन सॉल्ट की बिक्री करके निवल लाभ अर्जित किया है ।
25. सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में यह नोट किया गया कि कंपनी द्वारा उत्पादन लागत विवरण मासिक आधार पर तैयार किया जाता है । कंपनी ने इन मासिक उत्पादन लागत विवरणों से जांच अवधि का उत्पादन लागत विवरण समेकित किया है । कंपनी द्वारा छमाही आधार पर लाभ व हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार किया जाता है । प्राधिकारी

ने लेखा बहियों से कच्चे माल के विवरण तथा पैकिंग सामग्री की खपत एवं समाधान का सत्यापन किया। विनिर्माण व्यय के संबंध में यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा परिवर्तन पर किए गए व्यय का विवरण मासिक आधार पर रखा जाता है। विनिर्माण व्यय में वेतन संबंधी व्यय, प्रचालन व्यय, ऊर्जा बचत कार्यक्रम, आंतरिक परिवहन, अग्नि बीमा, किराये, संपत्ति कर, मरम्मत एवं अनुरक्षण, सुविधा आवाजाही, पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन, प्रयोगशाला व्यय, नमूनों, बड़े-खाते डाला गया दोषपूर्ण उत्पादन, मूल्यहास, शटडाउन व्यय आदि शामिल हैं। विक्रय एवं वितरण व्यय के संबंध में यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा विक्रय एवं वितरण व्यय का ब्यौरा मासिक आधार पर रखा जाता है। विक्रय एवं वितरण व्यय में कमीशन संबंधी व्यय, छूट, नमूने मालभाड़ा, विक्रय कीमत, विक्रय सहायता शुल्क शामिल है। एसजीए व्यय के संबंध में यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा प्रति माह एसजीए तथा ब्याज व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है। एसजीए तथा ब्याज व्यय में प्रशासनिक व्यय के स्वरूप के विभिन्न व्यय, अप्रत्यक्ष विक्रय व्यय तथा सामान्य व्यय शामिल है। प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा बेचे गए पीएचपीजी बेस तथा अन्य उत्पादों के बीच सभी व्ययों के आवंटन का सत्यापन किया। यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी के पास पूर्ण लेखा वर्षों अर्थात् 2004 तथा 2005 के अंकेक्षित आय विवरण उपलब्ध हैं। इसके अलावा कंपनी के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित लेखा परीक्षा समीक्षा के आधार पर जून में समाप्त अवधि के लिए आय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित था। अंतः कंपनी ने अपना आय विवरण एवं तुलन-पत्र जून, 2005 को समाप्त अवधि हेतु तैयार किया है। कंपनी ने जांच अवधि से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए जून, 2004 तथा जून, 2005 एवं जून, 2004, दिसंबर, 2004, जून, 2005, दिसंबर, 2005 तथा जुलाई 2004-जून, 2005 अवधि का आय विवरण उपलब्ध कराया।

26. जहां तक स्वयं की खपत, भारत को निर्यात तथा तीसरे देशों को निर्यात हेतु उत्पादन लागत के निर्धारण का प्रश्न है, कंपनी द्वारा उत्पादन लागत का विवरण उत्पादन स्तर की लागत को ध्यान में रखकर किया है। आबद्ध खपत को सकल उत्पादन लागत में से घटा दिया गया है। इस चरण में उत्पादन लागत उसी स्तर पर मानी गई है। अतः स्टॉक परिवर्तनों के समायोजन के पश्चात विक्रय लागत के निर्धारण के लिए

प्रत्यक्ष विक्रय व्यय, एसजीए तथा ब्याज जोड़ दिया गया है । इस प्रयोजनार्थ जांच अवधि के लिए निर्यातक की सत्यापित उत्पादन लागत पर विचार किया गया है । लागत का निर्धारण जांच अवधि के दौरान प्रमुख कच्चे माल की लागत, उसके खपत कारकों तथा भारित औसत कीमत के रूप में किया गया है । जांच अवधि के दौरान किए गए व्यय पर विचार करके परिवर्तन लागत का निर्धारण किया गया है । कारोबार राशि के अनुपात में विचाराधीन उत्पाद पर अनुपातिक रूप में कंपनी के एसजीए व्यय पर विचार करते हुए विक्रय, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय (एसजीए) को जोड़ा गया है । प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा अर्जित समग्र लाभ पर विचार करके लाभ का निर्धारण किया है । इस प्रकार मूल्यांकन किया गया सामान्य मूल्य **** अमरीकी डॉलर बनता है ।

27. जहां तक विक्रय का संबंध है, मैसर्स केएनसी, सिंगापुर द्वारा दो विक्रय मार्ग अपनाए जाते हैं- प्रत्यक्ष विक्रय एवं केएनके, जापान के माध्यम से विक्रय । बिक्री प्रत्यक्षतः ग्राहक को अथवा आयातक देश में एजेंट के माध्यम से की जाती है । भारत के मामले में सभी बिक्री भारत स्थित एजेंटों के माध्यम से की जाती हैं । कंपनी के मुख्यतः दो एजेंट हैं:- एपीसी कार्पोरेशन एवं संपर्क । यह भी पाया गया कि सभी मामलों में माल सीधे सिंगापुर से ग्राहक को जाता है । यदि माल का बीजक सीधे ग्राहक के नाम तैयार किया गया है, तो जापान को कमीशन प्राप्त होता है । यदि माल का बीजक केएनके, जापान द्वारा तैयार किया जाता है तो केएनके की मार्जिन के समायोजना के पश्चात् केएससी द्वारा केएनके हेतु बीजक तैयार किया जाता है । प्रत्यक्ष विक्रय में जापान द्वारा विपणन प्रयास किया अथवा नहीं किया जाता है । फिर भी उसे कमीशन का भुगतान किया जाता है । सिंगापुर में घरेलू बिक्री के मामले में भी (अन्य उत्पादों के लिए भी) विक्रय सहायता शुल्क का भुगतान किया जाता है । यह नोट किया गया कि जापान को भुगतान किए गए विक्रय सहायता शुल्क का ब्यौरा विक्रय विवरण में विक्रय विवरण शुल्क के रूप में विधिवत दर्ज किया गया । केएनके, जापान तथा केएससी, सिंगापुर की विक्रय बीजक राशि के बीच के अंतर को ज्ञात करके जापान के माध्यम से जापान द्वारा जोड़ी गई बिक्री मार्जिन का पता लगाया गया । कमीशन के संबंध में यह नोट किया गया है कि कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार की बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया गया, जिसमें भारत को की गई

बिक्री पर दिया गया कमीशन भी शामिल है । इसके अलावा, विभिन्न रिकार्डों से उधार अवधि की भी जांच की गई । शिपर बीजकों से समुद्री मालभाड़े पर किए गए व्यय का निर्णय किया गया । तथापि, एकाधिक पोत परिवहन द्वारा विक्रय किए गए माल के संबंध में शिपर द्वारा बनाए गए एक संयुक्त बीजक के मामले में समुद्री मालभाड़े का निर्धारण बीजक में शामिल भार के अनुपात में किया गया । समुद्री बीमे का निर्धारण बीमा पालिसी तथा भुगतान पत्र से किया गया । यह पाया और सत्यापित किया गया कि शिपर द्वारा जारी समुद्री मालभाड़े के बीजक में पतन व्यय अंतरदेशीय माल भाड़े तथा निर्यात से संबंधित समस्त व्यय शामिल किया गया है । इस प्रकार सभी प्रकार के व्यय को घटाने के बाद केएससी के लिए भारत हेतु कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है । प्रकटीकरण विवरण के अलावा घरेलू उद्योग ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की गोपनीयता का मुद्दा उठाया है और इस जांच में पहले किए गए अपने अनुरोध को दोहराया है । गोपनीयता के मुद्दे पर पिछले पैराग्राफों में विचार किया जा चुका है । दूसरी ओर प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में मैसर्स कनेका ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन का प्रतिवाद किया है । कंपनी ने दावा किया है कि निर्धारित पाटन मार्जिन गलत है और इसकी कारखाना द्वार पर निर्यात मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य तथा सीआईएफ निर्यात मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन से उत्पादन लागत तथा लाभ के मार्जिन के मद्देनजर समीक्षा की जानी अपेक्षित है । कंपनी द्वारा किए गए दावे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और यह पाया गया कि वास्तव में सीआईएफ निर्यात कीमत पर विचार करते समय टंकण संबंधी त्रुटि हो गई थी और इस अशुद्धि को ठीक कर लिया गया है । निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत से प्राधिकारी सहमत नहीं हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने आबद्ध खपत, भारत को निर्यात तथा तीसरे देशों को किए गए निर्यातों के संबंध में भिन्न-भिन्न उत्पादन लागत का दावा किया है । तथापि, प्राधिकारी द्वारा विभिन्न बाजारों (आबद्ध खपत सहित) के लिए भारित औसत उत्पादन लागत अपनाना उचित समझा गया । तथापि, यह पाया गया कि उत्पादन लागत की गणना में गणनात्मक त्रुटि हो गई थी, जिसे सुधार लिया गया है । प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में कनेका ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, आयातों के पहुंच मूल्य का प्रतिवाद किया । कंपनी का तर्क था कि जांच अवधि के दौरान सीमा शुल्क 20% तथा

15% के बीच था, अतः प्राधिकारी द्वारा बीजक दिनांक पर ध्यान देते हुए भारत औसत सीमाशुल्क पर विचार किया जाना चाहिए था । तथापि, इस संबंध में स्थायी रूप से प्रयुक्त पद्धति के अनुसरण में प्राधिकारी ने उक्त अवधि में निर्यातित मात्रा पर विचार न करते हुए जांच अवधि के दौरान लागू सीमाशुल्कों के सरल औसत पर विचार किया ।

28. मैसर्स केएससी, सिंगापुर के लिए पाटन मार्जिन 15.71% अथवा **** सी. डॉलर निर्धारित की गई है ।

परिवर्तित परिस्थितियों का स्थायी स्वरूप और विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा संभावित पाटन तर्क:

29. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के अनुसरण में यह जांच की गई कि क्या परिवर्तित परिस्थितियों को स्थायी स्वरूप की परिस्थितियां कहा जा सकता है अथवा क्या पाटनरोधी शुल्क वापस ले लेने पर पाटन पुनः प्राप्त होने की संभावना है । मैसर्स केएससी ने कहा है कि वर्तमान जांच अवधि में भारत को निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से अधिक है । घरेलू उद्योग का दावा है कि कच्चे माल की कीमत कम होने के आधार पर उत्पादन लागत कम होने का केएससी का दावा तथ्यों से परे है । घरेलू उद्योग का कहना है कि अधिकतम मामलों में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है और तुलनात्मक रूप से यह वृद्धि कतिपय संख्या के कच्चे माल की कीमत में गिरावट से काफी अधिक है । कच्चे माल की कीमतें अधिक होने, सॉल्वेंट कीमतें अधिक होने, अपरिष्कृत तेल की कीमतें बढ़ने से उपयोगी वस्तुओं की लागत बढ़ने, ऊपरी व्यय में सामान्य वृद्धि, एसजीएंड ए व्यय में **** % वृद्धि, जो केसी की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित की गई है, के साथ-साथ लेखांकन नीति में परिवर्तनों आदि के मद्देनजर पितृ कंपनी के व्यय के अनुषंगी कंपनियों को आवंटन से संचारित सामान्य मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन भी अधिक होगा ।

निर्यात कीमत में और कमी की कोई संभावना नहीं :

30. घरेलू उद्योग ने दिनांक 15 दिसंबर, 2005 के अपने गोपनीय प्रस्तुतीकरण में सिंगापुर से पीएचपीजी बेस की निर्यात कीमत का रुझान प्रस्तुत किया है। वित्त वर्ष 1998-99 अर्थात् पिछले सात वर्षों से कीमत रुझान में लगातार अधोगामी प्रवृत्ति दिखाई दी है और पीएचपीजी बेस की कीमत वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान **** अम.डॉलर/ मी.टन से घटकर वर्ष 2004-05 के दौरान **** अम.डॉलर/ मी.टन हो गई है अर्थात् वित्त वर्ष 1998-99 के बाद लगभग 48% की कमी आई है। निर्यातक का यह दावा कि कीमत में कमी कच्ची सामग्री की कीमत में कमी के कारण उत्पादन लागत में आई कमी की वजह से आई है, केएससी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। स्वयं केएससी के दावे के अनुसार कुछेक कच्ची सामग्रियों की कीमत में गिरावट केवल 25% तक की हुई है जबकि प्रमुख कच्ची सामग्रियों की कीमत में **** % तक की भारी वृद्धि हुई है। तदनुसार, निर्यात कीमत में आगे और कमी न होने की संभावना के बारे में केएससी का दावा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। तथापि, केएससी ने प्राधिकारी के समक्ष दर्ज किए गए अपने वास्तविक अनुरोधों के अनुसार विभिन्न करणों से कच्ची सामग्री की लागत में भारी कमी का दावा किया है।

भारत को निर्यात के संबंध में उसके व्यवहार का अंतिम स्वरूप :

31. मै. केएससी ने दावा किया है कि प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान वास्तविक पाटन मार्जिन और कीमतों के वर्तमान रुझान को ध्यान में रखते हुए पाटन की पुनरावृत्ति या उसके जारी रहने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी ने यह दावा किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पीएचपीजी बेस की निर्यात कीमत के आधार पर मूल जांच में पाटन मार्जिन का निर्धारण **** अम.डॉलर/ मी.टन किया था और पीएचपीजी की **** अम.डॉलर/ मी.टन के वर्तमान कीमत रुझान को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन में लगातार वृद्धि होगी और वह लगातार जारी रहेगी।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

32. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों की जांच की । घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पीएचटीएन की लागत संरचना उपलब्ध नहीं कराई गई है । यह भी तर्क दिया गया है कि पीएचटीएन की खरीद एक कंपनी से की गई है । यह भी तर्क दिया गया है कि पीएचटीएन की कीमत में जांच अवधि के बाद गिरावट आई है और इसलिए पाटन की संभावना है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह तर्क कि कनेका पीएचटीएन का उत्पादन करता है, वस्तुतः गलत है । पीएचटीएन का कोई उत्पादन नहीं होता है और कनेका, जापान द्वारा बाजार से उसकी खरीद की जाती है और कनेका, सिंगापुर को उसकी आपूर्ति की जाती है । यह तथ्य कि क्या पीएचटीएन की कीमत में गिरावट आई है या नहीं, जांचाधीन कंपनी से संबंधित वास्तविक मामला है । प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत पीएचटीएन की खरीद की सौदेवार ब्यौरे की जांच की है । मूल जांच अवधि के दौरान की गई खरीद के ब्यौरे की भी जांच की गई थी । यह पाया गया है कि कंपनी ने आपूर्ति का स्रोत **** से बदल कर **** कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप कीमत में भारी कमी आई है । यह भी पाया गया है कि कनेका, जापान ने अप्रत्यक्ष बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक बिक्री को हिसाब में लेने के बाद लाभ पर कनेका, सिंगापुर को बिक्री की है । इस प्रकार जांच से यह पता नहीं चला है कि घरेलू उद्योग का दावा वस्तुतः गलत है । यह भी उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक का दावा गलत होने की पुष्टि होती हो । यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि निर्यात कीमत में गिरावट आई है, इसलिए पाटन मार्जिन में वृद्धि होनी चाहिए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि निर्यात कीमत में गिरावट से पाटन मार्जिन में वृद्धि होगी । पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों से संबंधित होता है । यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों में गिरावट आई है ।

33. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कच्ची सामग्री की कीमत में वस्तुतः वृद्धि हुई है । तथापि, जांच से यह सिद्ध हुआ है कि कच्ची सामग्री की कीमत

में वस्तुतः गिरावट आई है (जापान के स्थान पर चीन जन.गण.से कच्ची सामग्री की खरीद के कारण)। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। तथापि यह नोट किया जाता है कि उत्पादन लागत में गिरावट न केवल आवेदकों के लिए आई है बल्कि घरेलू उद्योग के लिए भी आई है। वस्तुतः घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में गिरावट आवेदकों की उत्पादन लागत में गिरावट से कहीं अधिक आई है। तदनुसार घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पाटन में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि रोजगार में कमी आई है। लेकिन यह तर्क देने का कोई आधार नहीं है कि रोजगार में कमी से पाटन में वृद्धि होगी। तथापि, वास्तविकता यह है कि जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक बना रहा है। इसके अलावा निर्यातक के पास अपने देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की भारी क्षमता है और वे संबद्ध वस्तु की कोई घरेलू बिक्री नहीं करते हैं एवं भारत को हुए निर्यात उनके कुल उत्पादन तथा बिक्री का मामूली हिस्सा है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यद्यपि मै. केएससी के तर्क इस वादे पर आधारित हैं कि जांच अवधि के दौरान कोई पाटन नहीं किया गया है और पाटन के जारी रहने की कोई संभावना नहीं है, तथापि प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि वस्तु का भारत को निर्यात पाटन कीमतों पर किया गया है और सिंगापुर के मामले में पाटन मार्जिन काफी अधिक है तथा पटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने की संभावना है।

क्षति का जारी रहना :

34. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि :-

- (क) भारतीय उत्पादक याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निर्यातों के कारण सतत क्षति से पीड़ित था। निर्यात केवल अग्रिम लाइसेंस के तहत किए जा रहे थे और पाटनरोधी शुल्क की संदत्त कीमत घरेलू उद्योग के भारी मुनाफे से काफी अधिक थी।

- (ख) घरेलू उद्योग को वस्तु के संभावित पाटन से किसी भी हालत में क्षति नहीं पहुंच रही थी ।
- (ग) दौराला द्वारा किए गए व्यापक विस्तार से सतत क्षति का पता नहीं चलता है । याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के विस्तार के कारणों की व्यापक जांच करने का भी अनुरोध किया है ।
- (घ) यद्यपि कनेका द्वारा आयातों की पहुंच कीमत इस तथ्य के कारण बेंचमार्क से काफी कम थी कि निर्यात अग्रिम लाइसेंस के तहत किए गए थे और पाटनरोधी शुल्क की संदत कीमत उक्त बेंचमार्क से कम नहीं होनी चाहिए थी । दौराला को इस बेंचमार्क से कम पर बिक्री करने से किसी ने नहीं रोका है । यदि दौराला ने बेंच मार्क से कम पर बिक्री की होती तो उन्हें वित्तीय घाटा नहीं उठाना पड़ता । इससे यह सिद्ध होता है कि दौराला को हुई क्षति का कारण अलग है ।
- (ङ) दौराला द्वारा किया गया क्षमता बढ़ोत्तरी का दावा भ्रामक है । तथ्य यह है कि कंपनी ने संयंत्र की स्थापना हेतु दो चरणों में योजना तैयार की थी । जहां प्रथम चरण की स्थापना हो गई थी वहीं विस्तार का यह आरोप संयंत्र के द्वितीय चरण के अलावा कुछ भी नहीं है । वास्तव में इस तथ्य की वजह से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पूर्ववर्ती उत्पादन लागत, जो इस निर्धारण का आधार थी, असामान्य रूप से अधिक थी जिसमें अब काफी कमी आ जानी चाहिए थी ।
- (च) दौराला द्वारा उत्पाद का निर्यात भारत में उसकी बिक्री कीमत और अनेक देशों के लिए निर्यात कीमत से काफी कम कीमत पर किया जा रहा है । वस्तुतः भारी वित्तीय घाटे पर दौराला द्वारा विश्व बाजार में निर्यात करके कनेका के समक्ष अनुचित प्रतिस्पर्धा पेश की जा रही थी ।
- (छ) भारत सरकार ने हाल ही में यूरोप से उक्त उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया था । इसलिए घरेलू उद्योग पर पाटित न किए गए ऐसे आयातों के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

- (ज) पीएचपीजी बेस बनाने की दौराला की प्रौद्योगिकी उनके द्वारा विकसित नहीं की गई है बल्कि यूरोप से खरीदी गई है और इसलिए उन्हें लाइसेंसिंग फीस और/अथवा रायल्टी का भुगतान करना पड़ रहा होगा जिससे, उनका उत्पादन महंगा हो गया है ।
35. दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क के निरसन हेतु वर्तमान मध्यावधि समीक्षा सिंगापुर के एकमात्र निर्यातक के अनुरोध पर शुरू की गई है । ऐसे किसी मामले में लागू किया जाने वाला और जांच किए जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । इस प्रकार वास्तविक क्षति की मौजूदगी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता के लिए कोई पूर्वापेक्षा नहीं है । यद्यपि घरेलू उद्योग यह मानता है कि संबद्ध सामग्री के आयातों के परिणामस्वरूप उससे लगातार क्षति हुई है ।
36. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, तथा (ख) पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन उत्पादों के परिणामी प्रभावों दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है ।
37. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में समग्र रूप से या तुलनात्मक दृष्टि से पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । तथापि, चूंकि वर्तमान जांच मौजूदा शुल्क की मध्यावधि समीक्षा है, इसलिए जो बात जांच के लिए अधिक संगत है वह यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से आयात जारी रहेंगे या आयातों की पुनरावृत्ति होगी । आयातों की मात्रा और पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद भारत को निर्यात की गई वस्तु की कीमत को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावना है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में आगे और वृद्धि होगी ।

38. संबद्ध देशों, अन्य देशों से आयातों के बाजार हिस्से, भारत में मांग/खपत के संबंध में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तु की मांग इंगित करने के बाद किया गया था । भारत में मांग/खपत का आकलन आयातों के मूल्य और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री के रूप में किया गया था । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद इस बात की जांच की गई थी कि क्या संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि के अनुरूप आई है । अधिकारी द्वारा की गई जांच का ब्यौरा नीचे दिए गए पैराग्राफ में दर्शाया गया है ।

कीमतों पर प्रभाव:

39. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों में अत्यधिक ह्रास लाना या कीमत वृद्धि को रोकना है जिसमें अन्यथा पर्याप्त वृद्धि हो गई होगी । घरेलू उद्योग ने करों और शुल्कों, रिबेट, छूट तथा कमीशन एवं भाड़े तथा परिवहन को छोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार करते हुए निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण किया है । घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री मात्रा को इन गणनाओं में शामिल किया गया है । आयातों के पहुंच मूल्य की गणना 1% उतराई प्रभार तथा लागू मूल सीमा शुल्क के साथ भारत और सीआईएफ आयात कीमत पर विचार करते हुए की गई है । तुलना निवल बिक्री प्राप्ति और आयातों की पहुंच कीमत के बीच की गई थी ।
40. जहां तक कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर का निर्यातक संबद्ध सामग्री का निर्यात पाटित कीमत पर कर रहा है जिससे घरेलू उद्योग निर्यात कीमत की बराबरी करने के लिए अपनी कीमत कम करने के लिए बाध्य हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

41. घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच करने के बाद यह भी नोट किया जाता है कि पिछले वर्षों की तुलना में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन ऐसा रहा है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पुनः क्षति हो सकती है। यह इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग से जुड़े अनेक आर्थिक मानदंडों से आगे और स्पष्ट हो जाता है।
42. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि आयातों की पहुंच कीमत (पाटनरोधी शुल्क के बिना) क्षति रहित कीमत की तुलना में काफी कम है। आयातों की पहुंच कीमत कंपनी की घरेलू बिक्री कीमत से भी कम है। यह भी बताया गया है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री प्रस्तावित क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर करने के लिए बाध्य हुआ है। संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भी घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है और उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त या निरस्त किए जाने से संबद्ध देश से होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में और अधिक कटौती होगी जिससे क्षति की पुनरावृत्ति होगी।
43. आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि कीमत में कटौती का खतरा काफी अधिक है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का पर्याप्त औचित्य है, तथापि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के निरसन के प्रभाव और इस बात की भी आगे जांच की है कि क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में पर्याप्त कमी होगी या कीमत में वृद्धि रुकेगी जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक हो गई होती। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने उत्पादन की यूनिट लागत, निवल बिक्री प्राप्ति तथा लाभ/हानि के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। यह तर्क दिया गया है कि चीन जन.गण., सिंगापुर और यूरोपीय संघ से पाटित कीमतों पर आयात हो रहे थे जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। तथापि, घरेलू उद्योग की याचिका पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 20.9.2002 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं. 51/1/2001-डीजीएडी और 31.10.2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 122/2002-सी.शु. के तहत चीन जन.गण. तथा सिंगापुर से पीएचपीजी बेस के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था। बाद में

प्राधिकारी ने 7-3-2003 की अधिसूचना सं. 14/6/2002-डीजीएडी के तहत यूरोपीय संघ के मूल का था वहां से निर्यातित पीएचपीजी बेस के आयात पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाया था । चीन जन.गण. सिंगापुर एवं यूरोपीय संघ से पीएचपीजी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग कर सका और अपनी स्थापित क्षमता भी 240 मी. टन (पूर्ववर्ती जांच के समय) से बढ़ाकर 850 मी.टन प्रति वर्ष कर ली । यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करना है तो इससे घरेलू उद्योग को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे ।

प्राधिकारी द्वारा जांच:

44. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियम के अनुबंध- II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, तथा (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है ।
45. प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में उत्पादन या खपत की समग्र मात्रा के रूप में या उसकी या खपत की समग्र मात्रा के रूप में या उसकी तुलना में पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है । तथापि, चूंकि वर्तमान जांच मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए मध्यावधि समीक्षा है, इसलिए जिस बात की जांच करना संगत है वह यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमत पर आयातों की पर्याप्त मात्रा जारी रहेगी । घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कोई बिक्री न होने और भारत को निर्यात की कीमत को ध्यान में रखते हुए तथा भारत में निर्यात की पूर्ववर्ती मांग को भी ध्यान में रखते हुए सिंगापुर के निर्यातक के पास अतिरिक्त क्षमता हान के कारण इसकी संभावना काफी अधिक है ।
46. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटन से कीमत में भारी कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक ह्रास होगा या कीमतों में वृद्धि रुकेगी जो अन्यथा पर्याप्त स्तर

तक हो गई होती । जांच के बाद यह माना जाता है कि पाटित आयातों से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है ।

मांग का आकलन:

47. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खपत/मांग की गणना करने के लिए प्राधिकारी ने भारत में कुल आयातों में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा जोड़ी है । घरेलू उद्योग ने गौण स्रोत अर्थात् इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विसेज से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर आयात की मात्रा और मूल्य का निर्धारण किया है । प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस के सौदे-वार आंकड़े एकत्र किए हैं । आवेदकों, डीजीसीआईएंड एस और आईबीआईएस द्वारा सूचित आयातों की तुलना से यह पता चलता है कि आवेदकों द्वारा किए गए निर्यात का वास्तविक मूल्य डीजीसीआईएंड एस एवं आईबीआईएस द्वारा सूचित मात्रा से अधिक है अतः प्राधिकारी ने सिंगापुर से आयातों पर आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर विचार किया है । तथापि, अन्य देशों से हुए आयातों पर डीजीसीआईएंड एस के सौदे-वार आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है ।

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	140.79	105.99	80.88
बिक्री आबद्ध	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	381.23	726.28	830.12
घरेलू उद्योग की कुल बिक्री	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	207.37	277.75	288.35
संबद्ध देशों से आयात	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100.00	380.86	391.48	285.71
अन्य देशों से आयात	601	386	441	511
सूचीबद्ध	100.00	64.21	73.33	85.10
मांग	1033	1517	1795	1753
सूचीबद्ध	100.00	146.90	173.81	169.75

* गोपनीयता का दावा किया गया

उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश में संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित होती है और इसमें क्षति अवधि में 69% की वृद्धि हुई है ।

आयात की मात्रा एवं बाजार हिस्सा

48. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II में निम्नानुसार उपबंध हैं :-

"पाटित आयातों की मात्रा जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है -----"

49. यह नोट किया जाता है कि अति अवधि के दौरान सिंगापुर से पाटित आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा से सतत आयातों का पता चलता है । इसके अलावा पाटित आयातों में समग्र रूप में तथा उत्पादन एवं मांग की तुलना में भी वृद्धि प्रदर्शित होती है और उसके हिस्से में वृद्धि हुई है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
आयात				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूचकांक	100	380.88	391.91	286.03
कुल अन्य देश	****	****	****	****
सूचकांक	100	64.23	73.38	85.02
कुल आयात	737	904	974	900
सूचकांक	100	122.66	132.16	122.12
आयातों में बाजार हिस्सा				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूचकांक	100	310.29	296.43	233.95

कुल अन्य देश	****	****	****	****
सूचकांक	100	52.36	55.50	69.66
मांग	1033	1517	1795	1753
सूचकांक	100	146.85	173.77	169.70
मांग में बाजार हिस्सा				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूचकांक	100	259.10	225.34	168.36
अन्य देश	****	****	****	****
सूचकांक	100	43.71	42.20	50.14
कुल आयात	71.37	59.58	54.24	51.36
सूचकांक	100	83.48	76.00	71.96
घरेलू उद्योग	****	****	****	****
	100	141.18	159.83	169.89
घरेलू उद्योग का उत्पादन	****	****	****	****
सूचकांक	100	192	257	269
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयात				
सिंगापुर	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	196	152	105
अन्य देश	****	****	****	****
सूचकांक	100	33	28	31
कुल आयात	****	****	****	****
सूचकांक	100	63	51	45

यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से क्षति अवधि के दौरान पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा से सतत आयातों का पता चलता है ? इसके अलावा, आयातों में समग्र रूप में और उत्पादन एवं मांग की तुलना में वृद्धि प्रदर्शित होती है जोकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों, अन्य देशों से आयातों के बाजार हिस्से तथा भारत में मांग/खपत की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का निर्धारण किया है। भारत में आयातों तथा घरेलू उद्योग की घरेलू मात्रा के रूप में मांग/खपत का निर्धारण किया गया था। यह पाया गया था कि यद्यपि संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में परिणामी वृद्धि के साथ

अत्यधिक कमी आने की आशा है । वस्तुतः घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा हासिल करने की बजाय उसे गवाया है । साथ ही साथ संबद्ध देशों से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा कम होने की बजाय उसमें भारी वृद्धि हुई है ।

आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव:

50. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में इस बात की जांच की गई है कि क्या भारत में सामान उत्पादन की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा पर्याप्त स्तर पर कमी आएगी या उसमें वृद्धि रुकेगी जो अन्यथा काफी अधिक हुई होती । घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों का विश्लेषण किया गया था । निम्नलिखित तालिका से क्षति अवधि की तुलना में रुझान का पता चलता है :-

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
सिंगापुर से निर्यात कीमत	****	****	****	****
सूचकांक	100	87	95	110
सिंगापुर से आयातों की पहुंच कीमत	****	****	****	****
सूचकांक	100	84	77	84
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	****	****	****	****
सूचकांक	100	94	88	88
घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत	****	****	****	****
	100	105	104	104
जांच अवधि के लिए क्षति रहित कीमत				****
कीमत कटौती				
राशि				****

<input type="checkbox"/>				3-8%
%				
कम कीमत पर बिक्री				
<input type="checkbox"/>				****
राशि				
<input type="checkbox"/>				25-35%
%				

51. संबंधित उत्पाद की तुलना व्यापार के उसी स्तर पर असंबद्ध ग्राहकों को की गई बिक्री हेतु समस्त रिबेट एवं करों को छोड़कर निर्यातित उत्पाद के पहुंच मूल्य तथा घरेलू बाजार के लिए घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच की गई थी। घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया गया था। संबद्ध देश की सीआईएफ कीमत का समायोजन आयात के बाद लागू शुल्कों के लिए किया गया था। इस तुलना से यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान सिंगापुर के मूल की संबद्ध वस्तु की भारतीय बाजार में बिक्री उस कीमत पर की गई थी जिससे घरेलू उद्योग द्वारा इष्टतम से पर्याप्त कम कीमत की पेशकश किए जाने पर भी घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हुई थी। कीमत कटौती की सीमा काफी अधिक पाई गई थी। यह भी नोट किया जाता है कि समूची अति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत अत्यंत कम स्तर पर बनी रही। अतः प्राधिकारी का मानना है कि सिंगापुर से आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हो गई थी और घरेलू उद्योग की कीमत में उस स्थिति में भी ह्रास हो रहा था जब घरेलू उद्योग को निविष्टि की कीमतों में वृद्धि के कारण अपनी कीमत में वृद्धि करनी चाहिए थी।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव:

52. विगत की तुलना में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन ऐसा रहा है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होगी। यह घरेलू उद्योग से संबंधित अनेक आर्थिक मानदंडों से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है जैसाकि नीचे चर्चा की गई है।

बिक्री मात्रा:

53. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग पीएचपीजी बेस के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण ही अपने आरंभिक चरण से अभी उभरा है । यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा तो इससे सिंगापुर से सस्ते आयात होंगे और घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भारी कमी आएगी । क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में काफी वृद्धि हुई है ।

आयात तथा बिक्री और उसके रुझानों के बारे में ब्यौरे:

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
सिंगापुर से आयात	****	****	****	****
सूचकांक	100	380	391	286
अन्य देशों से आयात	****	****	****	****
सूचकांक	100	283	324	375
घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री	****	****	****	****
भारत में				
सूचकांक	100	450	603	626
भारत में कुल मांग	1032.7	1516.99	1794.9	1752.98
प्रवृत्ति	100.00	146.90	173.81	169.75
भारत में कुल मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	141.17	159.80	169.87

क्षमता उपयोग:

54. यह अनुरोध किया गया है कि पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग केवल (30-35%) था । तथापि, जांच अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद क्षमता उपयोग बढ़ी हुई स्थापित क्षमता पर बढ़कर 100% तक हो गया है । यदि पीएचपीजी बेस पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो इससे सिंगापुर से पाटित वस्तुओं की भरमार हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में भारी कमी आएगी ।

55. लाभप्रदता:

पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग ने विगत वर्षों की तुलना में अपने घाटों को कम किया है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन पर स्थायी लागत का मानकीकरण हुआ है और इससे उत्पादन लागत में कमी आई है। यद्यपि, यदि पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया गया होता तो यह निश्चित है कि इससे पाटित आयातों के कारण कम बिक्री मात्रा से घाटों में और अधिक वृद्धि होगी। इससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है और परिणामतः घरेलू उद्योग को और अधिक घाटा हो सकता है।

बिक्री कीमत और पीबीटी की प्रवृत्तियां:

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
बिक्री कीमत (रु./किग्रा.)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	89.19	83.40	82.75
कर पूर्व लाभ (लाख रु. में)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	(100.00)	(62.30)	(60.95)	(51.34)

यह नोट किया जाता है कि घाटे में मुख्यतः उत्पादन लागत पर आधारित अंतरण कीमत पर पीएचपीजीडीएस के उत्पादन हेतु संबद्ध सामग्री की आबद्ध खपत के कारण कमी आई है। यदि लाभप्रदता की तुलना बिक्री कीमत के आधार पर की जाए तो इन वर्षों में कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है।

नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव:

56. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु के लिए अलग से नकदी प्रवाह का ब्यौरा तैयार करना घरेलू उद्योग के लिए अत्यंत कठिन होगा। तथापि, जैसा कि उल्लेख और नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध सामग्री पर घाटा हो रहा है और वह प्रतिकूल नकदी प्रवाह का सामना कर रहा है।

माल सूची:

57. जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद माल-सूची का परिसमापन करने में सक्षम हुआ है ।

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
माल सूची	****	****	****	****
सूचकांक	100	81.78	6.43	6.20
बिक्री के % के रूप में माल सूची	****	****	****	****
सूचकांक	100	58.04	5.97	7.63

निवेश पर आय:

58. कीमत ह्रास के कारण घरेलू उद्योग अपने निवेश पर घाटा उठा रहा है और इस समय वह घाटे पर प्रचालन कर रहा है और उसे निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हो रही है । तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घाटे में कमी आई है । यह अनुरोध किया गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो घाटे में पुनः वृद्धि हो जाएगी और निवेश पर आय प्रतिकूलतः प्रभावित होगी ।

मजदूरी:

59. यह नोट किया जाता है कि घाटे के कारण घरेलू उद्योग अपने कर्मचारियों को मामूली वेतन वृद्धि ही प्रदान कर सका है ।

पूँजीगत निवेश जुटाने की क्षमता:

60. भारत में पीएचपीजी बेस की मांग घरेलू उद्योग की मौजूदा क्षमता से अधिक है और घरेलू उद्योग मूल कंपनी की सहायता से मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाकर घरेलू बाजार की संपूर्ण मांग को पूरा कर सकता है। तथापि, अतर्कसंगत कीमतों पर संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग बाजार से पूँजी जुटाने की स्थिति में नहीं है।

रोजगार (रोजगार स्तर, कथित पाटित आयातों के कारण कर्मचारियों की अस्थायी छटनी)

61. इस उत्पाद के लिए कार्यरत कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में इस तथ्य के बावजूद पिछले 3 वर्षों में कोई खास अंतर नहीं आया है कि कंपनी की बिक्रियों में वृद्धि हुई है और क्षमता बढ़ी है।

गंवाई गई संविदाओं या कम होती बिक्रियों का साक्ष्य:

62. यह अनुरोध किया गया है कि निर्यात कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण, आयातक घरेलू उद्योग को आयात कीमतों के बराबर कीमतें करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आगे यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग इतनी कम कीमत पर संबद्ध सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है और इतनी कम कीमत पर बिक्री करने पर डीओएल अपनी सीमान्त लागत भी वसूल नहीं कर पाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वह उपभोक्ता गंवा देगा।

लाभप्रदता (याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) और उद्योग के लिए लाभ स्तरों का पिछला विवरण)

63. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है घरेलू उद्योग अपनी शुरुआत से ही घाटे में चल रहा है। यद्यपि मात्राओं में वृद्धि हुई है तथापि कीमत की दृष्टि से घरेलू उद्योग किसी भी तरह से लाभ में प्रतीत नहीं होता है और कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है।

आयातों की मात्रा:

64. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है । तथापि, यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो आयातों की मात्रा में जबरदस्त उछाल आ सकता है जैसाकि पाटनरोधी शुल्क लगने से पहले हुआ था । पाटित आयात बाजार हिस्सा और बढ़ा सकते हैं ।

आयात की प्रवृत्ति:

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	380.46	391.48	285.71

पाटन की मात्रा:

65. पाटित आयात घरेलू उद्योग को किस सीमा तक क्षति पहुंचा सकते हैं इसके संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा यह दर्शाती है कि सिंगापुर के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन जांच अवधि के तब भी काफी अधिक है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

उत्पादन:

66. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से पहले घरेलू उद्योग का उत्पादन काफी कम था । पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से इसमें वृद्धि हुई । तथापि, यह अनुरोध किया गया है कि यदि शुल्क हटा लिया जाता है तो इसमें गिरावट आएगी ।

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
घरेलू उद्योगों का उत्पादन मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100.00	193.42	257.46	269.73

वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्षः

67. प्राधिकारी द्वारा जांच

पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का उल्लेख है (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव की दृष्टि से ऐसे आयातों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव । प्राधिकारी से इस बात की जांच करने की अपेक्षा की गई है कि क्या आयातों में समग्र रूप से या आयातक देश में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है । तथापि, यह देखते हुए कि वर्तमान जांच मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए मध्यावधि समीक्षा है, यहां यह जांच करना संगत है कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से पाटित कीमतों पर आयात अत्यधिक मात्रा में जारी रहेंगे । सिंगापुर में निर्यातक की अधिशेष क्षमता को देखते हुए और घरेलू बाजार में संबद्ध सामग्री की कोई घरेलू बिक्री नहीं होने के मद्देनजर तथा भारत में निर्यात की पूर्ववर्ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह सर्वाधिक संभावित स्थिति है । विगत समय में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन ऐसा रहा है कि पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग से संबंधित अनेक आर्थिक मापदंडों से और स्पष्ट हो जाता है । क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राएं पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान बढ़ गई हैं । यहां तक कि पाटित आयातों की सतत मौजूदगी के कारण देश के भीतर काफी मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग को अलाभकारी कीमतों पर निर्यात करने को बाध्य होना पड़ा है । यह भी कहा गया है कि वर्तमान समीक्षा के मध्यावधि समीक्षा जांच होने के कारण यह जांच करना अधिक संगत है कि क्या पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने से बिक्री मात्राओं के घटने की आशंका है । इस संबंध में घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि मौजूदा कीमत कटौती को देखते हुए यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को बिक्री मात्राओं में काफी घाटे का सामना करना पड़ेगा । प्राधिकारी ने घरेलू

उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है । यह देखा जाता है कि पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने से पहले घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग केवल 32% था, तथापि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में बढ़ी हुई स्थापित क्षमता पर 100% तक की वृद्धि हुई है । कीमत के संबंध में यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में लगातार गिरावट आई है । कीमतों में गिरावट काफी अधिक है । यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग उत्पाद का कम कीमत पर निर्यात कर रहा है । तथापि, घरेलू उद्योग यह मानता है कि देश में पाटित आयात की मौजूदगी के कारण उसे निर्यात के लिए मजबूर होना पड़ा है । घरेलू उद्योग की निर्यात मात्राएं देश में आयात की मात्रा से काफी कम हैं । यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग बड़ी मुश्किल से घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, घरेलू उद्योग के पास किसी भी कीमत जो उसे मिले से सामग्री का निर्यात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । लाभप्रदता के संबंध में पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में कम घाटा उठाया है क्योंकि उत्पादन बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन पर स्थिर लागत का मानकीकरण हुआ है जिसके फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी हुई है । तथापि, यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो यह निश्चित है कि पाटित आयातों के कारण कम बिक्री मात्रा के कारण घाटा और बढ़ेगा । इसके अलावा इसके परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन लागत होगी और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को और अधिक घाटे उठाने पड़ेंगे नकदी प्रवाह के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है । घरेलू उद्योग की नकदी प्रवाह की स्थिति पर पाटन का प्रभाव और नकदी प्रवाह पर शुल्क हटाए जाने का प्रभाव घरेलू उद्योग के नकदी प्रवाह में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टव्य होने की संभावना नहीं है । तथापि, घरेलू उद्योग की नकद लाभ की स्थिति का नकदी प्रवाह की स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा । घरेलू उद्योग के नकदी लाभ की स्थिति क्षति अवधि के दौरान काफी खराब हुई है । जैसाकि पहले बताया गया है कि सिंगापुर से निर्यातक पाटित कीमतों पर संबद्ध सामग्री का निर्यात कर रहा है जिससे निर्यात कीमत से बराबरी करने के लिए घरेलू उद्योग को कीमत घटानी पड़ी है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है । यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो घरेलू उद्योग द्वारा

अभी तक हासिल की गई मात्रा गंवा दी जाएगी और कीमतों में हास के अलावा, इससे घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय नुकसान होगा। निर्यातकों के रिकार्ड से संकलित आंकड़ों के प्रतिपादन से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि आयातों की पहुंच कीमतें (पाटनरोधी शुल्क के बिना) प्रस्तावित क्षति रहित कीमत की तुलना में काफी कम है। आयातों की पहुंच कीमत भी कंपनी की घरेलू बिक्री कीमत से कम है। घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में प्रस्तावित क्षतिरहित कीमत से काफी कम कीमत पर संबद्ध वस्तु को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा है। संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है और इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति/हटाये जाने की स्थिति में संबद्ध देश के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और तेज हो जाएगी और इससे क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

68. उत्पादन तथा उत्पादकता को छोड़कर उपर्युक्त क्षति संबंधी मानदंडों में से अनेक मानदंड यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से हो रहे आयातों से अभी भी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आयातों का पहुंच मूल्य प्रस्तावित क्षतिरहित कीमत से काफी कम है। औसत घरेलू बिक्री वसूली भी क्षति रहित कीमत से पर्याप्त कम है। अतः संबद्ध देश से संबद्ध सामग्री के आयात से कीमत प्रभाव अर्थात् कीमत कटौती तथा कीमत हास उत्पन्न हो रहा है। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से का घाटा उठाना पड़ा (मात्रात्मक प्रभाव)। इस प्रकार उपर्युक्त जांच के आधार पर यह मत व्यक्त किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के परिणामतः घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और यदि संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाए तो यह क्षति जारी रहने की संभावना है। अतः उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी का यह अभिमत है कि सिंगापुर से पाटित आयातों के आधार पर वास्तविक क्षति की निरंतरता निर्धारित की गई है।

क्षति की आवृत्ति:

69. वर्तमान जांच मध्यावधि समीक्षा जांच है जो निर्यातक के अनुरोध पर शुरू की गई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की आवृत्ति की मध्यावधि समीक्षा की अपेक्षाओं के संदर्भ में जांच की जानी अपेक्षित है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से पाटित आयात पहले ही घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं और यदि वर्तमान शुल्क को हटाया जाता है तो कीमत कटौती का दायरा और बढ़ जाएगा जिससे घरेलू उद्योग को और ज्यादा क्षति होने की अत्यधिक संभावना है। इसके अलावा घरेलू उद्योग का निष्पादन विचाराधीन अवधि के दौरान पहले से ही प्रतिकूल था तथा यह संभावना है कि पाटनरोधी उपायों के बिना संबंधित उत्पाद की अत्यधिक बढ़ी हुई मात्रा भारतीय बाजार में अत्यधिक कम कीमतों पर जहाज द्वारा भेजी जाएगी जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होगी। यह भी नोट किया जाता है कि चीन तथा सिंगापुर से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पहले ही क्षति हो रही है तथा सिंगापुर से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाने से भारतीय बाजार में और कीमत मंदी हो जाएगी क्योंकि घरेलू उद्योग के पास अपने उत्पादन को घटाने के बजाय पहले अपने बाजार हिस्से को कायम रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे आगे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षरण होगा।
70. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा है कि क्या आयात में निरपेक्ष रूप में अथवा आयातक देश में उत्पादन या खपत के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तथापि, यह मानते हुए कि वर्तमान जांच मध्यावधि समीक्षा है, यहां यह जांच करना प्रासंगिक है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर आयात अत्यधिक मात्रा में होना जारी रहेंगे। सिंगापुर निर्यातक के पास अतिशेष क्षमता को मानने की अत्यधिक संभावित स्थिति इस तथ्य के मद्देनजर है कि घरेलू बाजार में संबद्ध माल की कोई घरेलू बिक्री नहीं है तथा भारत को निर्यात अंक अन्य बाजारों में निर्यात की तुलना में कम रहना जारी है। यह भी नोट किया जाता है कि भारत को उनकी निर्यात कीमतों के स्तर से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास रहना जारी भी है।

71. उपर्युक्त जांच के आधार पर यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति होना जारी है तथा यदि संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो क्षति के जारी रहने की संभावना है।

72. उपर्युक्त अर/विचार करते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :

(क) सिंगापुर से भारत की संबद्ध वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिससे पाटन हुआ है तथा यदि संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने की संभावना है।

(ख) सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का होना जारी है।

(ग) प्राधिकारी सिंगापुर से आयातों के संबंध में यथा संशोधित पाटनरोधी शुल्क जारी रखना उपयुक्त मानते हैं क्योंकि इसे हटाने के फलतः पाटन तथा क्षति जारी रहेगी।

73. इसलिए प्राधिकारी सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएचपीजी बेस के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश को उपयुक्त मानते हैं। पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन के मार्जिन अथवा क्षति के मार्जिन, जो भी कम हो के बराबर होगी तथा जिसे लगाने पर घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का निराकरण हो जाता है। क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित बिक्री कीमत से तुलना की गई है। पाटनरोधी शुल्क नीचे कॉलम 9 में उल्लिखित राशि तथा अमरीकी डालर/किग्रा में आयात के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा बशर्ते पहुंच मूल्य प्रति किग्रा नीचे कॉलम 9 में विनिर्दिष्ट स्तर से कम हो।

क्र. सं.	उपशीर्ष	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2842.00	पीएचपीजी बेस	सभी श्रेणियां	सिंगापुर	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	11.25	किग्रा.	अम. डॉलर
2	2842.00	पीएचपीजी बेस	सभी श्रेणियां	कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	11.25	किग्रा.	अम. डॉलर

74. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आंकलनीय मूल्य तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3(क), 8(ख), 9 तथा 9(क) के तहत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सभी सीमाशुल्क होंगे ।
75. केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुरूप सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लाई जाएगी ।

क्रिस्टी एल. फेर्नांडेज, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 4th August, 2006
Final Findings

Subject : Mid-term Anti-dumping review investigations in the matter relating to imports of : D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) from Singapore

No. 15/14/2005-DGAD.—A. BACKGROUND OF THE CASE : Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), vide Notification No. 51/1/2001-DGAD dated 20th September, 2002, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of PHPG Base (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Singapore. The provisional findings were issued on 5th of June, 2002 and provisional duties were imposed by Central Government on 5th July 2002.

any interested party substantiating the need for a review, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, whether continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

In terms of the above provision, the producer and exporter M/s Kaneka Singapore Corporation, Singapore (KSC) filed a request for a changed circumstances mid-term review of the anti-dumping duty in force.

3. The producer and exporter of subject goods from Singapore M/s Kaneka Singapore Corporation (KSC), Singapore has listed the following grounds for changed circumstances review.

- The export price of KSC to India has significantly reduced.
- The Customs duty has been reduced from 35% to 20%.
- The dumping Margin has significantly declined and thus benchmark fixed in the original investigation should be reduced accordingly.
- The Cost of production has significantly declined in view of significant reduction in raw material price leading to reduction in the Normal value.
- The profits realized by the company have significantly declined which would be a tantamount to a decline in Normal value.

4. Having regard to the positive information provided by the applicant indicating the changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority considered that a mid-term review of the Anti-dumping Duty is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Rule 23 *supra*. Having decided to review the final findings notified vide Notification No.51/1/2001-DGAD dated 20th September 2002, the Authority initiated the investigations in terms of the Rules on 21st September 2005, to review whether continued imposition of the duty on imports of PHPG Base originating in or exported from the Singapore (also referred to as subject country) is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i) After initiation of the review the Authority sent questionnaires, along with the initiation notification, to exporters/producers in the subject country, and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information;
- ii) The Embassy of the subject country in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- iii) Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).
- iv) Investigation was carried out for the period starting from 01.04.2004 to 31.03.2005 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2000-01 to the end of POI.
- v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;. However, the DGCIS report has not been relied upon in this investigations as it was seen that exports quantity submitted by exporter are much higher in terms of quantity.
- vi) No response to the initiation notification was received from any other exporter except M/s Kaneka Singapore Corporation (KSC) and M/s Kaneka Japan, Japan (KNK). None of the interested parties except domestic industry have submitted response, in any manner, to the initiation notification subsequent stages of the investigations.
- vii) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.
- viii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- ix) The Authority examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible examine the injury suffered by them.

- x) The Authority also verified the data of the cooperating exporter and applicant for the subject review, to determine the normal value and dumping margin as per the Rules. Following verification, a copy of the verification report was sent to the exporters for their comments and the comments received have been incorporated in the final findings. A copy of the Non-confidential verification report was also placed in the public file for the information of all other interested parties.
- xi) The Authority held a public hearing on 3rd February 2006 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, exporters of the subject goods from the subject countries. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. Written submissions received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding to the extent these have been considered relevant to the investigation. In accordance with Rule 16 of the Rule supra, the essential facts/ basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 14th July 2006 and comments received on the same are duly considered in Final Findings.
- xii) **** In the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority after examining them under the rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'

6. The product involved in the original investigation and the current review is D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) falling under heading No.2942.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS classification. This classification, however, is indicative only and, in no way, binding on the scope of the present investigation. Predominantly 'D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base' (also to be read as per above mentioned synonyms) i.e. the 'subject material' (herein after referred as 'PHPG') is imported in to India which is converted in-situ to " D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt " (herein after referred as 'PHPGDS') by the various importers / manufacturers and used for the production of Amoxycillin and Cefadroxyl. (i.e. bulk drugs). In other words PHPG cannot be used directly for the production of Amoxycillin etc. It is only when PHPG is converted to PHPGDS, the same is used for the production of Amoxycillin etc. This conversion may either be done at the PHPG / PHPGDS manufacturers' end, or at the users end, i.e. producers of Amoxycillin etc.

7. There are no arguments on the product under consideration. As regards like article, it is noted that there is no significant difference in PHPG Base produced by the domestic industry and those imported from and sold in the subject country. PHPG Base produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of physical characteristics, functions and uses, specifications, distribution and marketing, pricing and tariff classification of goods. The consumer can use and are using PHPG Base imported from the subject countries and PHPG Base produced by the domestic industry interchangeably. Thus, PHPG Base produced by the domestic industry is considered as domestic like product to those imported from Singapore (subject country).

D. Domestic industry

8. In the original investigation the application was filed by M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Meerut (UP) now merged with M/s DCM Shriram Industries Ltd, unit; Daurala organics, Daurala. The applicant is the sole producer of the subject goods in India and have filed response to the review investigation as domestic industry. The Authority therefore holds that M/s.DCM Shriram Industries Ltd, unit; Daurala Organics, Daurala (DOL or Daurala Organics) constitutes a domestic industry within the meaning of the rules.

E. Arguments raised by various interested parties and Examination by the Authority

9. The domestic industry has submitted that there are insufficient grounds for review brought out by the petitioner in this case. M/s DCM Shriram Industries Limited, Unit- Daurala Organics, Daurala, Meerut (UP) (previously known as M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Dist. Meerut (UP) and the domestic industry (hereinafter referred to as DI or domestic industry has stated that the basic conditions in respect of subject material D (-) Phenyl Hydroxy Phenyl Glycine Base (hereinafter referred to as PHPG Base) have not changed, since the matter was finally investigated by the Designated Authority in the year 2002 and Customs Notification No.122/2002 dated 31.10.2002 was issued levying Anti-Dumping duty on import of the subject material from Singapore and China.

10. Article 11.2 of the WTO Agreement on Anti Dumping contains the following ingredients, for review of Anti Dumping levy:-

- (i) The authorities shall review the need for continuing any imposition of duty, where warranted.
- (ii)upon request by any interested party, which submits positive information substantiating for the need for review.
- (iii)where the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping.
- (iv) Whether the injury would be likely to continue or recur, if the duties were removed or varied or both.

11. Domestic Industry has submitted that the market conditions prevailing in India with respect to demand and supply for PHPG base and the economic conditions of domestic industry do not warrant any mid term review of imposition of duty. It has been further added that the most important criteria for review relates to whether the injury would be likely to continue or recur, if the duty were varied or removed or both. According to Article 11.2, reviews are prospective in nature, which require a projection of the likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, if the definitive duties were removed. This entails a counter-factual analysis of hypothetical future events based on projected levels of dumped imports, prices and impact on domestic producers. The question to be addressed is whether the domestic industry is likely to be injured again, if duties were lifted.

12. It has been further submitted by the domestic industry that they have provided the necessary factual details with regard to the performance of domestic industry in the Confidential version of their reply to the Authority vide their submission dated 15th December, 2005, which clearly demonstrate that the domestic industry is still injured and performance of the domestic industry would further deteriorate, if the Anti-Dumping duty is lifted.

13. The domestic industry has further added that dumping margin on the export made by KSC is claimed to be de-minimus in spite of both landed price of export and dumping margin in respect of export of KSC has significantly declined and therefore, benchmark must be reduced. KSC has claimed that landed price of import of inputs has significantly declined. It means that the export price has also declined significantly, which KSC also admits, in such case the dumping margin will rather increase instead of decrease as claimed by KSC. With regards to the export price, it has been submitted that the export price PHPG base from Kaneka, Singapore is declining is proof enough that goods are still being dumped in the Indian market.

14. It has been further submitted that KSC has claimed that their cost of production have reduced significantly due to significant reduction in raw material prices. KSC has claimed that the major raw material prices have reduced by almost 25% over the past 4 years. The analysis of Annexure-9 submitted on indexed basis shows that there is reduction in the prices of 7 nos. of raw materials by 2 to 17% during 2005 compare to 2001, while the prices of 8 nos. of raw materials has increased from 5 to 53% during the above period. It has been further submitted that It is a well known fact that over last 1 – 2 years, the prices of crude oil has gone up significantly from 2001 around US\$ 25 / barrel to as high as to US\$ 70 / barrel in recent period. Due to the same, not only the prices of solvents has gone up significantly, the cost of utilities has also almost doubled over the period. If a nominal increase of 5% in wages and other overheads is added, the cost of production will go up further at least by 10 to 15%. The claim of normal increase of 5% in the expenses is further substantiated based on the Annual Report of KC for financial year 2004-05 stating "Selling, general and administrative (SG&A) expenses were yen 85,673 million, up 5.3% year-on-year basis

15. The domestic industry has submitted that KSC source major raw material required for the production PHPG Base-PHTN from its parent company Kaneka Corporation, Japan (KC). The cost of PHTN itself is a major cost component for the production cost of PHPG Base for KSC. Accordingly, the cost of PHTN in the production cost of PHPG Base will definitely increase over the period due to the factors stated as above like increase in the solvent, utility prices, labour cost etc. The Domestic Industry has requested the Authority to go into the details of cost structure of PHTN produced by KC and must verify in detail the cost structure and transfer price mechanism of PHTN from KC to KSC.

16. It is submitted by the domestic industry that the averments of KSC that export price of Kaneka is above the cost of production and level of profit realized by the company has declined are contradictory. If earlier they were selling at less than the cost of production, they should have been making losses and when the export price has gone over and above the cost of production, as claimed by them, the profit should have risen which is in sharp contrast to their contention that profits have come down. This clearly indicates that they have reduced the prices in order to dump the goods in the Indian market.

17. On the other hand, the applicant has submitted that the fact whether or not inputs have declined is a matter of fact and is

based on the information/evidence/records of the applicant company. It is immaterial whether or not the Indian Producer has also experienced the same. Also, whereas the petitioners have argued about decline in the prices over the past 4-5 years, Indian Producer has been arguing between the investigation period and thereafter. It is not denied that the prices have increased within the investigation period and thereafter. The dumping margin determined by the Authority in the previously concluded investigation was also quite high and was unsupported by the information provided by the company. It has been further added that the cost of production of the company has declined in view of reduction in the prices of major inputs, significant increase in production, significant reduction in employment, decline in costs on account of depreciation, etc. Kaneka provided a comparison of cost of production for the previous investigation and present investigation, accounting for the differences with quantified reason and offered the same for verification at the time of visit.

- a) Prices of major input PHTN have declined, amongst other reasons, due to the fact that the company had switched its procurement source from **** to *****
- b) Since Kaneka has provided factual information, construction of normal value done by Daurala is meaningless.
- c) Petitioners have provided detailed transaction wise information not only with regard to export sales to India, but also in respect of exports to third countries. This is sufficient to establish whether the company was dumping the product to any of the third countries.
- d) Kaneka has provided invoice by invoice details of all expenses incurred on exports and therefore any claim of Daurala in this regard need be rejected.
- e) One of the possible reasons for high cost of production in the earlier investigation was the fact that in that investigation period, the company had produced very low volume of the product, thus resulting in high overhead costs incidence.

Examination by the Authority

18. The Authority has carefully examined various submissions made by the Interested parties in connection with the initiation of this review investigation.

19. Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall, from time to time, review the need for continued imposition of anti dumping duty and if it is

satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal.

20. Article 11.2 of the Agreement provides that the Authority shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review. Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately. The Authority holds that it has been its consistent practice to commence a review at the substantiated request of an interested party only after a lapse of one year from the date of imposition of Anti dumping duty and this requirement has been notified by a trade notice 1/99. In this instance case, the review has been accordingly initiated 26 months after the date of imposition of anti dumping duty.

21. The domestic industry has argued that under Article 11.2 of ADA read with Rule 23 of Indian Antidumping Rules, substantiation of grounds of review are mandatory and the applicant has failed to do so. Therefore, the initiation of the review is flawed. The Authority has analysed the arguments made by the various Interested parties and concludes that the "Applicant" had submitted positive information, inter alia that the export price of KSC to India has significantly reduced and the customs duty has been reduced from 35% to 20%. Further, the dumping Margin has significantly changed as explained in the earlier para and thus benchmark fixed in the original investigation should be revisited accordingly keeping in view of the fact that the cost of production has significantly declined in view of reduction in raw material price leading to reduction in the Normal value. On the basis of the foregoing, it is considered that initiation of mid term review has rightly been initiated by the Authority due to change in circumstances described in the foregoing. Subsequent to the disclosure statement, the domestic industry has submitted various arguments pertaining to the issue of confidentiality and adequacy of the data submitted by the applicant which have been examined by the Authority. They have argued that sufficient disclosures were not made by the applicant in their application and response to the questionnaire. It has also been submitted that the questionnaire response lacked indexed information and confidential replies

given in response to some of the questions were insufficiently disclosed. Further, full information with regard to related companies was not provided by the applicant and annual reports for the investigation period and preceding three years have not been provided to the Designated Authority. The submissions were examined by the Authority and having regard to requirements under Rule 7, the nature of product and the limited technology available with regard to production process, the fact that Kaneka is the sole producer and exporter from Singapore, it is held that the claims of the applicant with regard to confidentiality were justified. It is further clarified that sufficient information required for the purpose of determination of dumping margin was provided by the applicant. It is further confirmed that the applicant has also provided annual reports for the period ending June'04 and June'05 and three years preceding investigation period on the confidential basis (as they are not in public domain). Additionally, detailed financial information with regard to Kaneka, Japan not only concerning the company as a whole but also the division and the group relating to the product under consideration were provided by M/s Kaneka Japan. Investigations revealed that the information provided was on the basis of records maintained by the Company, which were found to be consistent with generally accepted accounting principles and the same reasonably reflected information with regard to the production, sales, costs and prices of the product under consideration. Information with regard to all world wide related companies was also provided. The issues with regards to the cost and price of raw materials and determination of dumping margin are analyzed in the following section.

E. DUMPING DETERMINATION

NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

22. Under Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act 1975, Normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country

or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Normal Value and Export Price

23. The Authority notes that M/s KSC does not have any domestic sales in Singapore. With regards to its sales to third countries, the applicant could not propose with justification as to which third country should be taken for the purpose of determination of normal value. After examination of the sales to third countries, the authority could not also determine the appropriate third country for the purpose of determining the normal value having regard to the criteria consistently followed by the Authority. In the absence of the above indicated basis of determination of Normal value the Authority had no option other than to determine the normal value based on the cost of production of the subject goods in Singapore by the company.

24. During the examination of the information submitted by the applicant and during verification process, it was noted that M/s KNK, Japan is the parent company of M/s Kaneka Sales Corporation, Singapore, the applicant in this investigation. In addition to substantial production activity, KNK Japan also undertakes sales of goods produced by its affiliates. Further, KNK purchases critical raw materials required for production of Base and Dane Salt for KNC, Singapore. However, verification team was shown that no service is provided free of cost to any affiliates, including KSC. While these transactions are priced more out of conventions, the costs associated with providing these services were found to be lower than the margins

retained by KNK. It was noted that KNK has made a net profit out of purchase and supply of raw materials for KSC and sales of Base and Dane Salt for KSC.

25. With regards to the normal value determination, it was noted that the company prepares cost of production statement on monthly basis. The company has consolidated cost of production statement for the POI from these monthly cost of production statements. The company also prepares six monthly profit & loss account and Balance Sheet. The Authority verified statement of raw materials and packing materials consumption and reconciliation from the books of account. With regards to manufacturing expenses, it is noted that the company prepares a statement of expenses incurred on conversion on monthly basis. The manufacturing expenses includes expenses on salaries, operating expenses, energy saving activities, inward transportation, fire insurance, rent, property tax, repairs & maintenance, facility movement, replacement of old equipment, laboratory expenses, samples, defective production written off, depreciation, shutdown expenses, etc. With regards to the selling and distribution expenses, it is noted that the company prepares a statement of sales & distribution expenses on monthly basis. Sales & distribution expenses includes expenses on commission, discounts, sample, freight, sales insurance, sales assistance fee. With regards to SGA expenses, it is noted that the company every month prepares a statement of SGA and Interest expenses. The SGA and Interest expenses includes various expenses in the nature of administrative expenses, indirect sales expenses and general expenses. The Authority verified the allocation of all expenses between PHPG Base and other products sold by the company. It was explained that the company has its audited income statement for the completed accounting years, i.e., 2004 and 2005. Further, the company was required to prepare an income statement for the period ending June on the basis of limited audit review by the auditors. Therefore, the company has prepared its income statement and balance sheet for the period ending June, 2005. The company has provided this income statement for the period June, 2004 and June, 2005 and for the period ending June, 2004, Dec., 2004, June, 2005, Dec., 2005 and July, 2004 – June, 2005 in order to compile data for the period of investigation.

26. With regards to determination of cost of production for self-consumption, exports to India and exports to third countries, the company has prepared cost of production statement by considering costs up to production level. Captive consumption has been reduced from this gross cost of production. Cost of

production has been considered at the same level at this stage. Therefore, direct selling expenses, SGA and interest have been added to determine cost of sales, after adjustment for stock changes. For the purpose verified cost of production of the exporter for the investigation period has been considered. Costs have been determined in terms of costs of major raw materials, consumption factors thereof and weighted average price in the period of investigation. Conversion costs have been determined by considering expenses incurred during the period of investigation. Selling, General and Administration (SGA) expenses have been added considering the SGA expenses of the company, apportioned on the product under consideration in the ratio of turnover. The Authority has determined profit by considering the overall profit earned by the company. The normal value so assessed come to US\$*****.

27. With regard to sales, the M/s KNC, Singapore follows two sales routes - direct sales and sales through KNK, Japan. The sales can be directly to the customer or through an agent in importing country. In case of India, all sales are through agents in India. The company primarily has two agents - APC Corpn. and Sampark. It was also noted that the goods in all cases move directly from Singapore to the customer. In case the goods have been invoiced directly to the customer, Japan gets a commission. In case goods are invoiced by KNK, Japan, KSC invoices on KNK, Japan after adjusting for margin of KNK. Sales made directly may or may not involve any marketing effort by Japan. Yet, a commission is paid to them. Even in case of domestic sales (for other products also) in Singapore, sales assistance fee is paid. It is noted that sales assistance fee paid to Japan has been duly reported in the sales statement as sales assistance fee. Margin added by Japan in respect of sales through Japan has been worked out from the difference between the sales invoice amounts of KNK, Japan and KSC, Singapore. With regard to the commission, it is noted that the company paid commission on various sales made, which included commission paid on sale made to India. Further, the credit period was examined from various records. Expenses on account of ocean freight has been determined from shipper's invoice. However, in case of one combined invoice by the shipper against goods sold by more than one shipment, ocean freight is determined in proportion to the weight involved in the invoice. The marine insurance has been determined from insurance policy and payment voucher. It is noted and verified that the port expenses, inland freight and all other expenses associated with exports are included in ocean freight invoice issued by the shipper. Thus, after deducting all expenses, the ex factory export price to India for KSC has been determined.

Further to the disclosure statement, the domestic industry has raised issues pertaining to the confidentiality pertaining to the information submitted by the exporter and has reiterated the submissions made by them earlier in this investigation. The issue of confidentiality has already been examined in the earlier paragraphs. On the Other hand, In response to disclosure statement, M/s Kaneka disputed the dumping margin determined by the Authority. The company claimed that the dumping margin determined was incorrect and was required to be reviewed with regard to cost of production & profit margin for the purpose of determination of normal value and CIF export price for the purpose of determination of ex-factory export price. Claims made by the company were examined by the Designated Authority and it was found that in fact there was a typographical error in considering CIF export price and therefore the same is corrected. The Authority does not agree with the cost of production claimed by the exporter. Authority notes that the company has claimed different cost of production for captive consumption, exports to India and exports to third countries. The Authority has however considered it appropriate to adopt weighted average cost of production for the different markets (including captive consumption). However, it was found that there was a calculation error in cost of production, which has also been corrected. In response to disclosure statement, Kaneka disputed the landed price of imports determined by the Authority. The company argued that the customs duties in the investigation period varied between 20% and 15% and therefore the Authority should have considered weighted average customs duties after taking into account the invoice date. The Authority has however considered simple average of customs duties applicable during the investigation period, as per consistent practice being applied in this regard, without considering the volumes exported during the relevant period.

28. The dumping margin for M/s KSC, Singapore has been determined as 15.71% or S\$ ****.

Lasting nature of the changed circumstances and likelihood of dumping- arguments by various interested parties

29. In accordance with the practices of the Authority, it was examined whether changed circumstances could be said to be of lasting nature or if there would chances of recurrence of dumping if the anti dumping duty is withdrawn. M/s KSC has submitted that export price to India is above normal value in the current POI. The domestic industry has claimed that the claim of KSC of lower cost of production, based on lower raw materials prices is far from the facts. The Domestic Industry has submitted that in maximum number of raw materials, the prices has increased and

comparatively, increase is much higher than the decrease in prices of few of the raw materials. The higher raw material prices, higher solvent prices, higher utilities cost due to increase in crude oil prices, lower capacity utilization, normal increase in overheads, ****% increase in SG&A expenses as reported in KC's Annual Report along with allocation of parent company's expenses to its subsidiaries in view of the changed in the Accounting Policy etc. will definitely increase the constructed normal value and in-turn, higher dumping margin.

No possibilities of further reduction in export price

30. The domestic industry in its confidential submission dated 15th December, 2005 has submitted the export price trend of PHPG Base from Singapore. The price trend from financial year 1998-99 onwards, in last 7 years continuously showing a downward trend and the price of PHPG Base has reduced from US\$ **** / MT during financial year 1998-99 to US\$ **** / MT during financial year 2004-05 i.e. reduction of about 48% since financial year 1998-99. The claim of exporter that the price reduction is due to reduction in cost of production because of decrease in raw materials is not substantiated by KSC. As per KSC's claim itself, decrease in some of the raw materials prices is only as high as 25% while the prices of major raw materials have increased substantially ranging upto ****%. Accordingly, the claim of KSC for no possibilities of further reduction in export price is contrary to the facts available on records. However, M/s KSC has claimed significant reduction in the raw material costs due to various reasons as actually recorded by it in its submissions to the Authority.

Lasting nature of its behavior in respect of exports to India

31. M/s KSC has claimed that considering the actual dumping margin during the proposed investigation period and present trend of prices, there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping. On the contrary, the respondent has claimed that the Designated Authority had determined dumping margin in original investigation based on the export price of PHPG Base of US\$ ****.4 / MT and looking the present trend of price of PHPG Base at US\$ **** / MT, it is obvious that dumping is continuously increasing and would continue and increase, if existing anti dumping duty is removed.

Examination by Authority

32. The Authority examined various arguments advanced by the domestic industry. It has been argued by the domestic industry that PHTN cost structure has not been provided. It is also argued that

PHTN has been purchased from an affiliated company. It is also argued that the PHTN prices have declined after the POI and therefore there is likelihood of dumping. The Authority notes that the argument of the domestic industry that Kaneka produces PHTN is factually incorrect. There is no production of PHTN and the same is procured from market by Kaneka, Japan and supplied to Kaneka, Singapore. The fact whether or not PHTN price has declined is a matter of facts pertaining to the company under investigation. The Authority has examined transaction wise details of purchase of PHTN submitted by the exporter. Details of purchases made during the original investigation period were also examined. It is found that the company has switched its supply source from **** to **** which has resulted in substantially lower prices. It is also found that the Kaneka, Japan has in fact sold to Kaneka, Singapore at profits, after taking into account indirect selling, general & administrative expenses. The investigation has thus not shown that the claim of the domestic industry is factually correct. It is also pointed out that the domestic industry has not provided any evidence which establishes that the claim of the applicant is incorrect. It has also been submitted that since the export price has declined, dumping margin can at best increase. The Authority notes that there is no basis to hold that the decline in export price would lead to increase in dumping margin. Dumping margin is linked to both normal value and export price. It is noted that both normal value and export price have declined over the period.

33. The Domestic industry argued that raw materials prices have in fact increased. The investigation has however established that the raw materials prices have in fact declined (because of shift in the sourcing of raw materials from Japan to China PR). The Authority has proceeded on the basis of records available. Further, the domestic industry argued the cost of production has increased. However, it is noted that the cost of production has declined not only for the applicants but also for the domestic industry. In fact, the cost of production of the domestic industry has declined far more substantially than the cost of production of the applicants. Additionally, the domestic industry argued that dumping is likely to increase as employment has gone down. However, there is no basis for the argument that decline in employment would lead to intensified dumping. However, the fact remains that dumping margin continues to be positive and significant during the POI. Moreover, the exporter has a huge capacity for the production of subject goods in their country and also they do not have any domestic sales of the subject goods and exports to India comprises a small fraction of the their total production and sales. The Authority thus concludes that whereas arguments of M/s KSC were based on the premise that there was no dumping during the investigation period and there was no likelihood of continuation of

dumping, the Authority has nevertheless determined that the goods have been exported to India at dumping prices and the dumping margin continues to be significant from Singapore and the dumping is likely to continue if the anti dumping duty is withdrawn.

Continuation of Injury

34. It has been submitted by the applicant that

- a) The Indian Producer was suffering no continued injury due to exports made by the petitioners. Exports were being made only under Advance Licence and anti dumping duty paid prices were significantly higher to permit huge profits to the domestic industry.
- b) Domestic industry in any case was not suffering injury to possible dumping of the goods.
- c) Huge expansion done by Daurala shows no continued injury. Petitioners also requested for detailed investigation into the reasons for expansion by the company.
- d) Whereas the landed price of imports by Kaneka were significantly below the benchmark due to the fact that exports were under advance licence, anti dumping duty paid price could not have been below the benchmark. Nothing prevented Daurala from selling below this benchmark. Should Daurala have sold below the benchmark, they could not have suffered financial losses. This establishes that the reasons for injury to Daurala are different.
- e) Capacity addition claim made by Daurala is misleading. The fact is that the company had planned two stage setting up of the plant. While the first stage was set up earlier, this alleged expansion was nothing but second stage of the plant. In fact, due to this, the cost of production earlier assessed by the Authority which formed the basis for determination was abnormally high, which should have now come down significantly.
- f) Daurala is exporting the product at prices significantly below their selling price in India and export price to a number of countries. In fact, Daurala was causing unfair competition to Kaneka in world market by exporting at huge financial losses.
- g) Govt. of India had recently revoked anti dumping duties on the product from Europe. Therefore, impact of such undumped

imports on the domestic industry must also be taken into account.

- h) Daurala's technology to make PHPG Base is not developed by them but bought from Europe and so they might be paying licensing fee and/or royalty which makes their product expensive.

35. On the other hand, the domestic industry has contended that present mid term Review for revocation of antidumping duty on PHPG base has been initiated on the request of sole exporter from Singapore. In such a case, the test to be applied and examined is whether the cessation of antidumping duty in force is likely to lead to the continuation or recurrence of the injury to the domestic industry. Thus, the existence of material injury is not the pre-requisite for continuation of antidumping duty even though domestic industry considered that the imports of the subject material have resulted in continued injury to them.

36. Article 3.1 of the ADA and Annexure-II of the A.D. Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports.

37. With regard to the volume of the dumped imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. However, given that the present investigation is a Mid Term Review of existing duties, what is more relevant to examine is whether cessation of Anti dumping duty would result in continuance of imports or recurrence of imports. Given the volume of imports and the level of prices at which the goods have been exported to India inspite of existence of anti dumping duty, it is likely that the volume of imports would further increase in case the present Anti dumping duties are withdrawn.

38. The market share of imports from the subject countries, imports from other countries and market share of domestic industry in relation to demand / consumption in India were determined after assessing the demand of the subject goods in India. Demand / consumption in India were assessed as the sum of imports and domestic sales of the domestic industry.

After imposition of anti dumping duty, it was examined if the market share of imports from the subject country declined with the increase in the market share of the domestic industry. Their examination by the Authority are produces in the paragraph below.

Effect on prices:

39. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Domestic industry has determined net sales realization considering selling price of domestic industry, excluding of taxes and duties, rebates, discounts & commissions and freight & transportation. Entire sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1% landing charges and applicable basic customs duty. The comparison was done between net sales realization and landed price of imports.

40. With regards to factors affecting prices, it is noted that the exporter from Singapore is exporting the subject material at the dumped price, which may be compelling the domestic industry to reduce its prices to match the export price and in turn, resulting into the losses to the domestic industry.

41. It is also noted after examining the performance of the domestic industry that the performance of the domestic industry over the past has been such that revocation of Anti dumping duty would result in recurrence in injury to the domestic industry. This is more than evident from a number of economic parameters relating to the domestic industry with regard to situation of the domestic industry over the period.

42. It has been submitted by the domestic industry that the landed prices of imports (without the Anti dumping duty) are significantly low as compared to non-injurious price. The landed price of the imports is also lower than the domestic selling price of the company. It has been added that the domestic industry is forced to sell the subject goods well below the proposed non-injurious price in the domestic market.. The landed price of the imports from subject country is still under cutting the prices of the domestic

industry even Anti dumping duty is in forced and causing material injury to the domestic industry. In the event of cessation / revocation of anti dumping duty, the imports of subject country would intensify the under cutting the prices of domestic industry, thereby leading to recurrence of injury.

43. It has been further added that the threat of price under cutting is significant and is per se sufficient to justify continuance of anti dumping duty. It has been further submitted that effect of dumped imports would further depress the prices to significant degree or prevent price increases, which otherwise would occur to a significant degree. For the purpose, the domestic industry has provided the information with regard to unit cost of production, net sales realization and unit profit / loss. It has been argued that imports were coming from China PR, Singapore and European Union at dumped prices, which were causing injury to the domestic industry. However, at the request of domestic industry in their petition, the Designated Authority after examination had imposed Antidumping duty on the import of PHPG base from China PR and Singapore vide its final findings notification no. 51/1/2001-DGAD Dt. 20.09.2002 and vide custom notification no. 122/2002-Customs Dt. 31.10.2002. Later on, Anti-dumping Duty was also imposed by the Designated Authority on import of PHPG base originating in or exported from European Union vide its Notification No. 14/6/2002-DGAD Dt. 07.03.2003. After the imposition of Anti dumping duty on the imports of PHPG from China PR, Singapore and European Union, the domestic industry could utilize its capacity and even has increased the installed capacity from 240 MT (at the time of previous investigation) to 850 MT per annum. It is claimed that if the Anti-dumping duty were to be withdrawn, it will result in serious consequences for the domestic industry.

Examination by the Authority

44. Article 3.1 of the ADA and Annexure-II of the A.D. Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports.

45. The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing country. However, given that the present investigation is mid term review for continuation of existing Anti dumping duty, what is relevant to examine here is whether the imports at dumped prices would continue in significant volume

in the event of revocation of Anti-dumping duty. This is the most likely situation given the surplus capacity with exporter from Singapore in view of no domestic sale of the subject material in the domestic market and the level the export prices to India also, keeping in mind previous volume of export in India.

46. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether dumping is resulting into significant price under cutting as compared to the prices of like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. It is considered after examination that dumped imports have caused adverse price effect on the domestic industry during the POI.

Assessment of demand

47. For the calculation of the Domestic consumption/demand of the product under consideration, the Authority added the sales volume of the domestic industry to the total imports into India. The domestic industry has determined import volume and value based on the data collected from secondary source i.e. International Business Information Services. The Authority collected transaction wise data from the DGCI&S. Comparison of imports reported by the applicants, DGCI&S and IBIS shows that the actual volume of exports made by the applicants is higher than the volumes reported by DGCI&S and IBIS. Therefore, the Authority has considered imports from Singapore on the basis of the information provided by the applicants. However, imports from other countries have been considered on the basis of DGCI&S transaction wise data.

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Sales of Domestic industry *	****	****	****	****
Indexed	100.00	140.79	105.99	80.88
Sales Captive	****	****	****	****
Indexed	100.00	381.23	726.28	830.12

Total sales of domestic industry	****	****	****	****
Indexed	100.00	207.37	277.75	288.35
Imports – Subject Country*	****	****	****	****
Indexed	100.00	380.46	391.48	285.71
Imports – Other Countries	601	386	441	511
Indexed	100.00	64.21	73.33	85.10
Demand	1033	1517	1795	1753
Indexed	100.00	146.90	173.81	169.75

* Claimed confidential

From the above table, it is concluded that the demand of the subject goods in the country shows positive growth and increased by 69 % in the injury period.

Import volumes and market share

48. With regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under :-

“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India

49. It is noted that volume of dumped imports from Singapore has increased in absolute terms during the injury period. It is also noted that the volume of imports shows continued imports. Further, the dumped imports shows an increase in absolute terms and also in relation to production and demand and its share increased as is evident from the table below

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Imports				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	380.88	391.91	286.03
Total Other Countries	****	****	****	****
Index	100	64.23	73.38	85.02
Total Imports	737	904	974	900
Index	100	122.66	132.16	122.12
Market Share in Imports				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	310.29	296.43	233.95
Total Other Countries	****	****	****	****
Index	100	52.36	55.50	69.66
Demand	1033	1517	1795	1753
Index	100	146.85	173.77	169.70
Market Share in Demand				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	259.10	225.34	168.36
Other Countries	****	****	****	****

241095/06-9

Index	100	43.71	42.20	50.14
Total Imports	71.37	59.58	54.24	51.36
Index	100	83.48	76.00	71.96
Domestic industry	****	****	****	****
	100	141.18	159.83	169.89
Production of Domestic industry	****	****	****	****
Index	100	192	257	269
Imports in relation to production of domestic industry				
Singapore	****	****	****	****
Index	100	196	152	105
Other Countries	****	****	****	****
Index	100	33	28	31
Total Imports	****	****	****	****
Index	100	63	51	45

It is noted that volume of dumped imports from Singapore has increased in absolute terms during the injury period. It is also noted that the volume of imports shows continued imports. Further, the imports shows an increase in absolute terms and in relation to production and demand increased as is evident from the table above.

The Authority has determined market share of imports from the subject countries, imports from other countries and market share of domestic industry in relation to demand / consumption in India. Demand / consumption in India were assessed as the sum of imports and domestic sales of the domestic industry. It was found that whereas the market share of imports from the subject countries was expected to decline significantly with a consequent increase in the market share of domestic industry after imposition of Anti dumping duty, In fact, the domestic industry rather than gaining market share, lost market share. At the same time, dumped imports from the subject country, rather than losing market share, has increased significantly its market share.

Price effect of imports

50. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market an analysis of import prices over the injury period was made. The table below shows the trend over the injury period-

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Export Price from Singapore	****	****	****	****
Index	100	87	95	110
Landed Price of imports from Singapore	****	****	****	****
Index	100	84	77	84
Selling price of the domestic industry	****	****	****	****
Index	100	94	88	88
Cost of production of the domestic industry	****	****	****	****
	100	105	104	104
Non injurious price for the POI				****
Price undercutting				
□ Amount				****
□ %				3-8%
Price underselling				
□ Amount				****
□ %				25-35%

51. A comparison for product concerned was made between the landed value of exported product and the average selling price of the domestic industry for domestic market net of all rebates and taxes for sales made to unrelated customers, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. The CIF prices of the subject country concerned were adjusted for post importation applicable duties. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in Singapore were sold in the Indian market at prices which were significantly undercutting the domestic industry's prices even in a situation where the domestic industry was already offering significantly sub-optimal prices. The extent of price undercutting was found significant. It is also noted that the prices of the domestic industry remained at suppressed level throughout the injury period. The Authority therefore holds that the imports from Singapore were significantly undercutting the prices and were at the same time depressing the prices of the domestic industry in a situation where the domestic industry should have increased its prices due to increases in the input prices.

Impact of the dumped imports on the domestic industry

52. The performance of the domestic industry over the past has been such that revocation of anti dumping duty would result in recurrence of injury to the domestic industry. This is more than evident from a number of economic parameters relating to the domestic industry, as discussed herein below.

Sale volume

53. It has been submitted that the domestic industry has just come out of its nascent stage only due to imposition of the anti dumping duty on the import of the PHPG base. If the anti dumping duty were to be withdrawn, this will result into the cheap imports from Singapore and will reduce the sales volume of the domestic industry significantly. The sales volume of the domestic industry have increased significantly during the injury period.

Details about Imports and Sales and trends thereof
(Unit MT)

	2002-03	2003-04	2004-05	ROI
Import from Singapore	****	****	****	****
Index	100	380	391	286

Import from Other countries	****	****	****	****
Index	100	283	324	375
Sales by Domestic Industry in India	****	****	****	****
Index	100	450	603	626
Total Demand In India	1032.7	1516.99	1794.9	1752.98
Trend	100.00	146.90	173.81	169.75
Share of Domestic Industry in Total Demand In India	****	****	****	****
Trend	100.00	141.17	159.80	169.87

Capacity utilization

54. It has been submitted that before the imposition of Anti-Dumping Duty on PHPG Base, the capacity utilization for the domestic industry was only (30-35%) , however, after imposition of the Anti dumping Duty capacity utilization during POI has increased upto 100% on the enhanced installed capacity. If the existing anti dumping duty on PHPG base is withdrawn, this will result into opening up of floodgates of the dumped goods from Singapore, and will result into substantial decrease in the capacity utilization.

55. Profitability

After the imposition of Anti dumping duty on PHPG base, the domestic industry has reduced its losses compared to previous years as the production has increased resulting into normation of the fixed cost on higher production, in turn resulting into the lower cost of production. However, if anti dumping duty were to be withdrawn, it is sure that losses will further increase, due to lower sales volume on account of dumped imports. It may result into higher production cost and as a consequence result into more losses to the Domestic .

Trends of selling Price and PBT

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Selling Price (Rs./Kg.)	****	****	****	****
Trend	100.00	89.19	83.40	82.75
Profit Before Tax (Rs.Lacs)	****	****	****	****
Trend	(100.00)	(62.30)	(60.95)	(51.34)

It is noted that losses have reduced mostly due to captive consumption of the subject material for the production of PHPGDS at a transfer price based on cost of production. If the profitability is compared based on selling price, the prices in the years are showing a declining trend.

Adverse effect on Cash Flow

56. It has been submitted that it will be very difficult for the domestic industry to prepare the cash flow for the subject material separately. However, as already mentioned and noted, the domestic industry is incurring losses on the subject material, and is facing adverse cash flow.

Inventory

57. As evident from table given below, the domestic industry has been able to liquidate inventories after imposition of Antidumping Duty.

Details of Inventory (Unit in MT)

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Inventory	****	****	****	****
Index	100	81.78	6.43	6.20
Inventory as a % of sales	****	****	****	****
Index	100	58.04	5.97	7.63

Return on investment

58. Due to depressed prices, the domestic industry is incurring losses on its investment and currently, running its operation at losses and having a negative return on investment. However, losses have come down after imposition of Antidumping Duty. It has been submitted that if Anti-dumping duty is withdrawn, losses would again increase and the return on investment will be adversely affected.

Wages

59. It is noted that because of the losses, the domestic industry is able to provide only the nominal increment to its employees.

Ability to raise the capital investment

60. The demand of the PHPG Base in India is more than the existing capacity of the domestic industry and domestic industry could cater to entire demand of the domestic market by debottlenecking of existing capacities through support of the parent company. However, due to dumped imports from the subject country at unreasonable prices, the domestic industry is not in position to raise the capital from the market.

Employment (employment levels, lay-off of employees due to increased alleged dumped imports)

61. The numbers of employees of the company dedicated for this product has not changed significantly since last 3 years in spite of the fact that the sales of the company have increased and capacity has been added.

Evidence of lost contracts or declining sales

62. It has been submitted that because of the sharp price fall in export prices, the importers are forcing the domestic industry to match the imported prices. It has been further submitted that domestic industry is not in a position to provide the subject material at such a low price, and by selling at such low prices, DOL cannot even recover the marginal cost, resulting in loss of customers.

Profitability (history of profit levels for the petitioner(s) and industry):

63. As mentioned earlier domestic industry is operating at loss from its beginning itself. Though, volumes have increased, on the price front domestic industry does not seem to have gained at all and the company is continuously incurring losses.

Quantum of Imports

64. Quantum of imports has increased despite imposition of the Anti dumping duty. However, if the Anti-dumping duty is revoked, the quantum of imports might jump significantly as it was before the imposition of anti dumping duty. Dumped imports may further gain the market share.

Trend of Imports

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Import from	****	****	****	****

Subject Country				
Trend	100.00	380.46	391.48	285.71

Magnitude of Dumping

65. Magnitude of dumping as the indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that dumping margin determined against Singapore is substantial for the POI, even when the Antidumping Duty is in force.

Production

66. Production of the domestic industry before imposition of Anti dumping duty was very low. It increased after imposition of the anti dumping duty. However it has been submitted that the same would decline if anti dumping duty is withdrawn.

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Production of domestic industry MT	****	****	****	****
Trend	100.00	193.42	257.46	269.73

Conclusions on material injury

67. Examination by the Authority

Article 3.1 of the ADA and Annexure-II of the A.D. Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The Authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing country. However, given that the present investigation is mid term review for continuation of existing Antidumping duty, what is relevant to examine here is whether the imports at dumped prices would continue in significant volume in the event of revocation of Anti-dumping duty. This is the most likely situation given the surplus

capacity with exporter from Singapore in view of no domestic sale of the subject material in the domestic market and the level the export prices to India also, keeping in mind previous volume of export in India. The performance of the domestic industry over the past has been such that revocation of Anti dumping duty would result adversely to the domestic industry. This is more than evident from a number of economic parameters relating to the domestic industry with regard to situation of the domestic industry over the period. With regards to Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales, it is seen that the sales volumes of the domestic industry have gone up considerably during the POI after imposition of the Anti dumping duty. It has been submitted that the present review being Mid Term Review investigations, what is more relevant to examine is whether revocation of present Anti dumping duties would potentially result in decline in sales volumes. Domestic industry submits, in this regard, given the level of existing price undercutting, the domestic industry would be faced with significant loss of sales volumes, should the present Anti dumping duties be revoked. The Authority has examined the injury parameters concerning domestic industry. It is seen that before the imposition of Anti dumping duty on PHPG Base, the capacity utilization for the domestic industry was only ****%, however, after imposition of the Anti dumping duty capacity utilization during POI has increased significantly on the enhanced installed capacity. With regards to the prices, however, it is seen that the selling price of the domestic industry has continuously declined. The decline in the prices is significant. It is argued that the domestic industry is exporting the product at lower prices. However, domestic industry considers that it has been compelled to export only because of presence of dumped imports in the country. Export volumes of the domestic industry is far lower than the import volumes in the country. Given that the domestic industry is finding it difficult to sell the subject goods in the domestic market, there is no other option for the domestic industry other than to export the material at whatever prices it can get. With regards to the profitability, after the imposition of Anti dumping duty on PHPG Base, the domestic industry has reduced its losses compared to previous year as the production has increased resulting into normation of the fixed cost on higher production, which in turn has resulted in the lower cost of production. Indeed, it is noted that if Anti dumping duty were to be withdrawn, losses would further increase, due to still lower sales realization on account of dumped imports. It will further result into higher production cost and as a consequence more losses to the domestic industry. With regards to the cash flow, it is contended that domestic industry is a multi product company. Impact of dumping on the cash flow situation of the domestic industry or impact of revocation of duty on cash flow may not be directly visible in the cash flow of the domestic industry. Cash profits of the domestic industry have shown very significant

deterioration over the injury period. As already stated that the exporter from Singapore is exporting the subject material at dumped price, which is compelling the domestic industry to reduce its prices to match the export price and in turn, resulting into losses to the domestic industry. If the anti dumping duty is withdrawn, the volume gained by the domestic industry so far will be lost and in addition to suppressed prices, this will result into the huge financial losses to the domestic industry. A perusal of data compiled from exporters record clearly demonstrates that landed prices of imports (without the Anti dumping duty) are significantly lower as compared to non-injurious price. The landed price of the imports is also lower than the domestic selling price of the company. The domestic industry appears to be forced to sell the subject goods well below the proposed non-injurious price in the domestic market. The landed price of the imports from subject country is still under cutting the prices of the domestic industry even when anti dumping duty is in force and the extent of price undercutting is considered significant. This has caused material injury to the domestic industry. In the event of cessation / revocation of anti dumping duty, the imports of subject country would intensify the under cutting the prices of domestic industry, thereby leading to continuation of injury.

68. Most of the above injury parameters except the production, sales and productivity shows that the imports from the subject country is still causing material injury to the domestic industry. The landed price of imports is far below the proposed non-injurious price. The average domestic sales realization is also well below the proposed non-injurious price. Thus the imports of subject material from the subject country is giving a price effect i.e. price under cutting and price suppression. The volume of imports from subject country has also increased resulting to the loss of market share of the domestic industry (volume effect). Thus, on the basis of the above examination, it is held that domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from subject country and injury is likely to continue if anti dumping duty from subject country is withdrawn. Thus, on the basis of the above examination, the authority holds that a continuation of material injury has been determined on account of dumped imports from Singapore.

Recurrence of injury

69. The present investigations are the mid term review investigations initiated at the behest of the exporter. It is noted that recurrence of injury to the domestic industry is required to be

examined in the context of the requirements under Mid Term Review. In this regard, it is noted that the dumped imports from Singapore are already undercutting the prices of the domestic industry to a very significant extent and should the present duties be revoked, the extent of price undercutting would further increase, which would most likely result in further increased injury to the domestic industry. Further, the performance of the domestic industry was already adverse during the period under consideration and it is likely that without anti dumping measures in place considerable increased volumes of the product concerned would be shipped in the Indian market at very low prices, undercutting the domestic industry prices. It is also noted that the domestic industry is already suffering injury as a result of dumped imports from China and Singapore and removal of present Anti dumping duty from Singapore would cause a further price depression on the Indian market, as the domestic industry has no other option but first to try to maintain its market share rather than reduce its production. This would in turn further erode the profitability of the domestic industry.

70. It is noted that the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing country. However, given that the present investigation is mid term review what is relevant to examine here is whether the imports at dumped prices would continue in significant volume in the event of revocation of Anti-dumping duty. This is the most likely situation given the surplus capacity with exporter from Singapore in view of the fact that there is no domestic sale of the subject material in the domestic market and exports to India continue to small as compared to their exports to other markets. It is also noted that the level of their the export prices to India also continue to depress the domestic industry's prices.

71. On the basis of the above examination, it is held that domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from subject country and injury is likely to continue if anti dumping duty from subject country is withdrawn.

72. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (a) The subject goods have been exported to India from the Singapore below its normal value resulting into dumping and there is a likelihood of continued dumping of subject goods from Singapore if anti dumping duty from subject country is withdrawn.
- (b) The Domestic Industry continues to suffer material injury on account of the dumped imports of the subject goods from Singapore.
- (c) The Authority considers it appropriate that anti dumping duties is required to be continued as modified in respect of imports from Singapore, as withdrawal thereof would lead to continuation of dumping and injury.

73. The Authority therefore considers it appropriate to recommend the continuation of anti-dumping duty on imports of PHPG Base originating in or exported from Singapore. The amount of anti-dumping duty shall be equal to the margin of dumping or margin of injury, whichever is less and which if levied would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed price of imports has been compared with the non-injurious selling price of the domestic industry determined for the period of investigation. The anti dumping duty shall be the difference between the amounts mentioned in column 9 below and the landed value of imports in US\$/Kg provided the landed price per Kg is less than the amount specified in the column 9 below.

S. No	Sub-Heading	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2942.00	PHPG Base	All grades	Singapore	Any Country	Any Producer	Any Exporter	11.25	Kg	US\$
2	2942.00	PHPG Base	All grades	Any Country	Singapore	Any Producer	Any Exporter	11.25	Kg	US\$

74. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962

and all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

75. An appeal against the order of Central Government shall lie before Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Addl. Secy. & Designated Authority